



अगर आप किसी की मदद कर रहे

हैं, और बदले में कुछ पाने की उम्मीद कर रहे हैं, तो आप दया नहीं बल्कि व्यापार कर रहे हैं।

बी.के. शिवानी

माही की गूँज

www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

वर्ष-05, अंक - 41

(साप्ताहिक)

खवासा, गुरुवार 13 जुलाई 2023

पृष्ठ-8, मूल्य-5 रुपए

चोरी कबूलवाने के लिए पुलिस ने दलित युवक को उल्टा टांग कर मारा, अधमरा कर पुलिस ने पैसे लेकर घर छोड़ा

पीड़ित परिवार घायल को लेकर चौकी पहुँचे, खुले आम पुलिस पर रिश्तत सहित गंभीर आरोप लगाए

कार्यवाही के डर से रात भर गूँज की खबर डिलीट करने की चलती रही मशक्कत, बात नहीं बनी तो पीड़ित परिवार पर दबाव बना निपटारे का प्रयास



गूँज के कैमरे पर पीड़ित के परिजन चोट के निशान दिखाते हुए।



करवड़ चौकी पर पदचर्य हेड कास्ट्रोल 14 हजार लेकर राजेश गेहलोत खुद अग्ने इस निजी वाहन में पीड़ित को घर छोड़ कर आए।

पर गूँज की टीम जब करवड़ चौकी पर पहुँची तो पीड़ित के परिजनों ने आप बीती सुनाई और किस तरह से पुलिस द्वारा ज़्यादाती की गई बताया। पीड़ित भी वमशिकल बोल पा रहा है और उसने बताया कि, किस तरह से करवड़ और सारंगी पुलिस द्वारा बेदुई से मारपीट की, मामला बिगड़ता देख चौकी प्रभारी रूखमणी अहिरवार पहले ही चौकी से निकल चुकी थी।

खबर डिलीट करने के लिए रात भर तक चलता रहा प्रयास, नहीं जमा मामला तो पीड़ित के

परिवार पर बनाया दबाव

खबर गूँज के यूट्यूब चैनल पर प्रकाशित होने के बाद पेटलावद थाना सहित करवड़, सारंगी चौकी पर अधिकारियों की गाज गिरने की वृथा

हो चुकी थी। जिससे बचने के लिए पुलिस ने गूँज के प्रतिनिधि सहित गूँज कार्यालय तक रात भर खबर हटाने का दबाव बनाया। इस दौरान पुलिस के स्थानीय अधिकारी ये कहते रहे कि, पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि, खबर डिलीट होगी तो ही कार्यवाही से बच सकते हैं। लेकिन सफलता नहीं मिलने पर पुलिस पीड़ित सहित पूरे परिवार को करवड़ चौकी पर लाकर मामले में समझौता करने का दबाव बनाया और अपने बचाव में पीड़ित के परिवार से अपने पक्ष में लेख पढ़ कर वीडियो बना लिए। इस दौरान कुछ पत्रकारों को भी बुलाकर पीड़ित का वीडियो देकर खबर प्रकाशित करने की कोशिश की लेकिन ज़्यादातर पत्रकारों ने खबर का खण्डन करने से मना कर दिया।

पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल, सीधी में पीड़ित के शपथ पत्र के बाद भी हुई कार्यवाही

पूरे मामले में पुलिस की भारी लापरवाही और

ज्यादाती सामने आ रही है। पुलिस महकमे की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, जो क्षेत्र में हो रही अपराधिक वारदातों को ट्रेस कर अपनी साख बचाने के लिए जबन लोगो पर चोरी की वारदात मढ़ कर चोरी की वारदातों का खुलासा कर खुद की पीठ थपथपा लेती है। लेकिन उसकी पूरी हकीकत अलग होती है जो इस तरह से सामने आती है। सीधी कांड में पहले से सरकार घिरी हुई है और वहाँ पीड़ित के शपथ पत्र के बाद भी आरतोपी पर कार्यवाही कर उसके घर पर बुलडोजर चलाया गया। ऐसे में झाबुआ जिले में दलित युवक के साथ हुई बेहमरी से पिटाई के मामले में झाबुआ पुलिस ने कोई कार्यवाही जबाबदार पुलिस वालों पर नहीं की है। जिससे एक बार फिर शिवराज सरकार फिर सकती है। क्या सीधी मामले की तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस दलित युवक को न्याय दिलाने के लिए इसके भी पूरा पक्षों या ये महज मीडिया की सुविधियों में आने के लिए एक दिखावा किया जाता है।

माही की गूँज, पेटलावद/करवड़

मध्यप्रदेश सरकार के एसटी एसी वर्ग हितोपी सरकार होने का दावा एक खोखला नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से इस प्रकार की घटनाएँ सामने आ रही, जिससे सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। झाबुआ जिले में एक बार फिर पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है यहाँ पेटलावद थाना क्षेत्र की करवड़ चौकी पर एक दलित युवक को चोरी का आरोप कबूलने के लिए अमानवीय तरीके से उल्टा टांग कर मारपीट की गई, पुलिस ने इस दलित युवक पर चोरी की वारदात कबूलने और किसी दूसरे व्यक्ति का नाम बताने का दबाव बनाया। युवक द्वारा चोरी नहीं कबूलने के बाद पुलिस ने युवक को अधमरी हालत में करवड़ चौकी का हेड कास्ट्रोल अपने निजी वाहन से घर छोड़कर आया जिसके लिए चौदह हजार की वसूली की गई। परिवार का आरोप है कि, करवड़ चौकी प्रभारी रूखमणी अहिरवार के इशारे पर

जबरन बूटे आरोप में युवक को फसाते की कोशिश की गई।

राधा-कृष्ण मंदिर पर हुई चोरी, खुलासे के लिए परेशान पुलिस

विगत दिनों करवड़ राधा-कृष्ण मंदिर पर हुई चोरी और मूर्ति खंडित करने के मामले में सीसीटीवी में कैद हुई चोरों की पहचान के चक्कर में पुलिस करवड़ चौकी क्षेत्र के ग्राम सुल्तानपुर निवासी बंदू पिता हरीश हितोत को पेटलावद थाना प्रभारी और करवड़ चौकी प्रभारी रूखमणी अहिरवार ने पुलिस बल के साथ शुक्रवार देर रात 12 बजे घर का दरवाजा रिश्तेदार बताकर खुलवाया और पूरे परिवार को कब्जे में लेकर पूरे घर की तलाशी ली। फिर युवक बंदू को पुलिस अपने साथ चौकी ले आये जहाँ उसके साथ बुरी तरह मारपीट की गई। उसके बाद उसको सारंगी चौकी ले जाया गया जहाँ उसके साथ अमानवीय

तरीके से मारपीट की गई। पुलिस जब युवक से चोरी नहीं कबूलवा सकी तो शनिवार रात को युवक को सारंगी चौकी से घर छोड़ा गया जिसके लिए पुलिस ने परिवार से पैसे लिए। सबसे बड़ी बात पुलिस ने मारपीट के बाद युवक को एक हेड कास्ट्रोल राजेश गेहलोत के निजी वाहन से उसके घर भेजा और उसका प्राथमिक इलाज तक नहीं करवाया।

चौकी पर चल रहा था विवाद, गूँज की टीम पहुँची तो पीड़ित और परिजनों ने बताई आप बीती

रविवार को सुबह पीड़ित के परिजन गम्भीर हालत में पीड़ित को लेकर चौकी करवड़ पहुँच गए जहाँ पुलिस द्वारा बिना किसी जुर्म के इस तरह से मारपीट करने वाली करवड़ और सारंगी पुलिस सहित थाना प्रभारी पेटलावद पर कार्यवाही की मांग कर रहे थे। जानकारी मिलने



चौकी पर पीड़ित की पत्नी चौकी प्रभारी और हेड कास्ट्रोल पर पैसे मांगने का आरोप लगाती हुई।



अधमरी हालत में चौकी करवड़ में सोया बंदी हितोत।

'सीधी पेशाब कांड': विधानसभा में हुआ जमकर हंगामा

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा सीधी में पेशाब घटना को लेकर आदिवासियों पर कथित अत्याचार और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद

बुधवार को तय समय से तीन दिन पहले अनिश्चित काल के लिए (बिना किसी तारीख के) स्थगित कर दी गई। सीधी पेशाब कांड आदिवासियों पर कथित अत्याचार महाकाल लोक निर्माण में भ्रष्टाचार और सतपुड़ा भवन अग्निकांड पर चर्चा की मांग करते हुए कांग्रेस सदस्य सदन के बीचोबीच आ गए और भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगाए।

कांग्रेस का आरोप है कि, आरोपी प्रवेश शुक्ला भाजपा का सदस्य है। कुछ कांग्रेस सदस्य अपने द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग करते हुए सदन के वेल में बैठ गए। हंगामे के बीच अध्यक्ष गिरिश गौतम ने अनुपूरक बजट सहित सदन का सूचीबद्ध कामकाज उठाया, जिसे बिना किसी चर्चा के ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।

बाद में एमपी के संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद स्पीकर ने विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। यह विधानसभा का आखिरी सत्र था क्योंकि इस वर्ष के अंत में मद्र में विधानसभा चुनाव होने हैं।

राहुल गांधी को मिला अब नया ठिकाना

नई दिल्ली। मानहानि केस में सजायापना होने के कारण कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी। इसके बाद उन्हें मिला सरकारी आवास भी खाली करा लिया गया था। वह अपनी माँ के साथ नई दिल्ली में 10 जनपथ वाले बंगले में रहने लगे थे। अब खबर आ रही है कि वह दक्षिणी दिल्ली को अपना नया ठिकाना बना सकते हैं। उनके निजामुद्दीन ईस्ट बी2 इलाके में शिफ्ट होने की संभावना है। राहुल गांधी जिस तीन बीएचके वाले मकान में रहेंगे वह दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के परिवार का है। शीला दीक्षित ने अपने जीवन के आखिरी वर्ष इसी घर में बिताए थे। वह 1991 से 1998 तक इस घर में रहें। 2015 के बाद वह फिर उसी फ्लैट में शिफ्ट हो गए।

हाल ही में उनके बेटे संदीप दीक्षित ने एक अनौपचारिक नोटिस जारी कर अपने परिचितों को उसी इलाके में अपना निवास स्थान ए5 में शिफ्ट करने की सूचना दी। राहुल गांधी को 2019 के मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद इस साल मार्च में लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने 22 अप्रैल 2023 को अपना आधिकारिक बंगला खाली कर दिया। वह अस्थायी रूप से अपनी माँ सोनिया गांधी के साथ चले गए। दिल्ली समेत देशभर से सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने राहुल गांधी को रहने के लिए अपने घर देने की प्रेरणा दी थी।

एसडीएम की करतूत ने फिर शर्मशार किया झाबुआ जिले को, हॉस्टल निरीक्षण के बहाने छात्राओं से की अश्लील हरकत

माही की गूँज, झाबुआ

एसडीएम सुनील कुमार झा की अश्लील हरकत से एक बार फिर झाबुआ जिला प्रदेश नहीं अपितु देशभर में सुर्खियों में आ खड़ा हुआ है। कठने को मध्यप्रदेश के पश्चिमी छोर पर बसे इस आदिवासी बाहुल जिले को लेकर सरकार कई तरह से कल्याण करने की कोशिश करने में लगी हुई है। मगर यहाँ आने वाले अफसर इस जिले को बड़ा लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से लगातार जिला सुर्खियों में बना हुआ है। अधिकारियों के भ्रष्टाचार की कहानियों से अखबार के पन्ने भरे पड़े हैं। ऐसा भी नहीं है कि, इनका विरोध नहीं होता। कई बार राजनीतिक पार्टियों से जुड़े जिले के आला पदाधिकारी अधिकारियों की शिकायत को लेकर मुखर रहे हैं। जिसके परिणाम कई आिकारियों के तबादलों के रूप में सामने भी आए हैं। अब सवाल यह है कि, सरकार का तंत्र इस हद तक गिर गया है की वह नाबालिग स्कूलों छात्राओं को अपना निशाना बना रहा है। इधर एसडीएम सुनील कुमार झा की बात करें तो यह कोई पहला मौका नहीं है जब वे सुर्खियों में आए हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही अवैध रेत परिवहन के मामले में एसडीएम पर आलीराजपुर जिले के एक भाजपा नेता भद्रु पचाया ने दलाल के जरिए लाखों रुपये की अवैध वसूली के आरोप लगाए थे। इस मामले में भी झा लंबे समय तक सुर्खियों में रहे थे। इस अवैध वसूली मामले ने अवेध उतखनन और माफिया राज से जुड़े कई चौकाने वाले खुलासे सामने लाकर खड़े कर दिए थे। माही की गूँज ने इस मुद्दे को बेबाकी से उठाया था माफियाओं के भोपाली कनेक्शन तक को उजागर किया था।

ताजें मामले में एसडीएम सुनील कुमार झा 9 जुलाई रविवार को दोपहर बाद हॉस्टल निरीक्षण के लिए निकले थे। इस दौरान उन्होंने रास्ते में ही नवीन आदिवासी कन्या आश्रम का निरीक्षण करने के लिए अपना वाहन रोक दिया। इस दौरान उन्होंने आश्रम परिसर में खेल रही बालिकाओं से चर्चा की और हॉस्टल का निरीक्षण करने की बात कही। इस हॉस्टल में 6टी से 8वीं तक की 50 आदिवासी छात्राएँ रहती हैं। छात्राओं के एकात्रित होने के बाद वे छात्राओं के साथ अंदर चले गए। निरीक्षण के दौर एसडीएम ने पहले अधीक्षिका को बाहर कर दिया

और पांच नंबर के रूम में पहुँच गए। यहाँ छात्राओं से बातचीत करते हुए सवाल-जवाब के दौरान वे बेडूटस किया। एक छात्रा को बेडूटस करते हुए अपने साथ पलंग पर बैठाया और एसडीएम ने बदनियति से बालिका की कमर को हाथ लगाया। एसडीएम सुनील झा के यहाँ से रवाना होते ही छात्राओं ने पूरी घटना हॉस्टल अधीक्षिका को बताई। अधीक्षिका ने सहायक आयुक्त निशा मेहरा को इसकी जानकारी दी। सहायक आयुक्त ने कलेक्टर तन्वी हुड्डा को इस बारे में तबादलों के रूप में सामने भी आए हैं। अब सवाल यह है कि, सरकार का तंत्र इस हद तक गिर गया है की वह नाबालिग स्कूलों छात्राओं को अपना निशाना बना रहा है। इधर एसडीएम सुनील कुमार झा की बात करें तो यह कोई पहला मौका नहीं है जब वे सुर्खियों में आए हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही अवैध रेत परिवहन के मामले में एसडीएम पर आलीराजपुर जिले के एक भाजपा नेता भद्रु पचाया ने दलाल के जरिए लाखों रुपये की अवैध वसूली के आरोप लगाए थे। इस मामले में भी झा लंबे समय तक सुर्खियों में रहे थे। इस अवैध वसूली मामले ने अवेध उतखनन और माफिया राज से जुड़े कई चौकाने वाले खुलासे सामने लाकर खड़े कर दिए थे। माही की गूँज ने इस मुद्दे को बेबाकी से उठाया था माफियाओं के भोपाली कनेक्शन तक को उजागर किया था।

दिलवाई थी। वर्तमान में सुनील झा के मामले में राजनीतिक पार्टियों ने भी एसडीएम को इस हरकत को शर्मशार करने वाला बतया। स. ए. ए. मीडिया पर हो रही चर्चाओं को अगर सामने रखें तो यह मामला राजनीतिक षडयंत्र भी बताया जा रहा है। हालाँकि इस मामले में खुलकर कोई बात राजनीतिक दखल की नहीं की जा रही है। इधर मंगलवार को एसडीएम सुनील झा के खिलाफ शासकीय सेवा से बर्खास्त करने की मांग का ज्ञापन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अवर कलेक्टर को दिया। कांग्रेस ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया इस मामले पर दी। इस पूरे मामले में कलेक्टर तन्वी हुड्डा और पुलिस अधीक्षक अगस जैन की सराहनीय भूमिका में नजर आए। कलेक्टर और एसपी ने इस पूरे मामले में सभी कार्यवाही की जो जरूरी थी। जिस तरह से इस मामले को कलेक्टर, एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्परता से निपटारा है। यह सराहनीय तो है, लेकिन अब उम्मीद कुछ ज्यादा है और आमजन प पीड़ित यह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि, अन्य मामलों में भी कलेक्टर, एसपी इस तरह की तत्परता दिखाएँ।

चुनाव से पहले शिवराज का एक और दांव

भोपाल। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के बाद पंचायत प्रतिनिधियों के लिए सौगात का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, जिला पंचायत, जनपद पंचायत के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, उप सरपंच, पंच आदि के मानदेय में तनू गुना वृद्धि की जा रही है। इसके साथ ही वाहन भत्ता भी बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्विरोध चुनी गई 705 पंचायतों को 55 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि जारी कर दी गई है।

जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा उप सरपंच एवं पंच के मानदेय में लगभग 3 गुना वृद्धि की जाएगी। जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 11 हजार 100 रुपए से बढ़कर 35 हजार रुपए और वाहन भत्ता 43 हजार से बढ़कर 65 हजार रुपए किया जाएगा। अब जिला पंचायत अध्यक्ष को 54 हजार 100 रुपए प्रतिमाह के स्थान पर एक लाख रुपए प्रतिमाह मानदेय, वाहन भत्ता सहित मिलेगा। जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 9 हजार 500 रुपए से बढ़कर 28 हजार 500 रुपए और वाहन भत्ता 9 हजार से बढ़कर 13 हजार 500 रुपए किया जा रहा है। अब जिला पंचायत उपाध्यक्ष को 18 हजार 500 रुपए प्रतिमाह के स्थान पर 42 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय, वाहन भत्ता सहित मिलेगा। जनपद पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 6 हजार 500 रुपए से बढ़कर 19 हजार 500 रुपए प्रतिमाह किया जा रहा है। जनपद पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 4 हजार 500 रुपए से बढ़कर 13 हजार 500 रुपए प्रतिमाह किया जा रहा है। सरपंच का मानदेय 1 हजार 750 रुपए प्रतिमाह से बढ़कर 4 हजार 250 रुपए प्रतिमाह किया गया है। उप सरपंच और पंच को 600 रुपए वार्षिक मानदेय मिलता है, जिसे 3 गुना बढ़कर एक हजार 800 रुपए किया जा रहा है।

हवाई यात्रा पर भाजपा सरकार ने कितना खर्च किया...?

भोपाल। मध्य प्रदेश में इसी वर्ष के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले अभी विधानसभा का मौनपूरा सत्र चल रहा है। इस सत्र के दौरान राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि सरकार ने गुजरे साढ़े चार महीनों में 12.74 करोड़ रुपए प्लेन और हेलिकॉप्टरों को किराए पर लेने में खर्च किया है। यह जानकारी खुद राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा के सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक मेवाराज जाटव के द्वारा पूछे गए एक जवाब में लिखित तौर से इस बात की जानकारी दी है।

कांग्रेस विधायक ने पूछ था कि मुख्यमंत्री, उनके मंत्री और सरकारी अधिकारियों ने इस साल 1 फरवरी से लेकर 15 जून तक हवाई यात्रा पर कितना खर्च किया है। इसपर एक लिखित जवाब में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस समय अवधि के दौरान 12.74 करोड़ रुपए विमान और चॉपर को हायर करने में खर्च किये गये।

सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि, चॉपर और प्लेन राज्य सरकार से जुड़े फर्म से लिए गए थे। यह हेलिकॉप्टर जस्कर और उपलब्धता के आधार पर लिए गए थे। इस समय अवधि के दौरान 127.5 घंटे सरकारी हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही साढ़े चार घंटे 123.28 घंटे के लिए इस्तेमाल किया गया और प्लेन का इस्तेमाल 168 घंटों के लिए किया गया।

सूचना अधिकार से निकली जानकारी, सरकारी स्कूलों में रिजल्ट सुधारने की फर्जी कोशिशों का हुआ खुलासा

कमजोर बच्चों की उपस्थित कम बताकर कर दिया जाता है प्राइवेट, शिकायत का नहीं हुआ अब तक कोई निराकरण, बच्चों के घर वालों को अनुपस्थिति की नहीं दी जाती जानकारी

माही की गूंज, पेटलावद/बामनिया।

सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मिली जानकारी के बाद सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं के वार्षिक परीणाम सुधारने के लिए कमजोर बच्चों को प्राइवेट करने के फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ है। हालांकि ये खेल वर्षों से सरकारी स्कूलों में लगातार जारी है और बच्चों के परिजनों के द्वारा इस मामले में आवाज नहीं उठाने के कारण हकीकत सामने नहीं आई। मामला विकास खण्ड की शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बामनिया का है जहां एक बच्ची के प्राइवेट होने के बाद के आगे की पढ़ाई में आई परेशानी के बाद इस मामले की शिकायत खण्ड शिक्षा अधिकारी पेटलावद को लिखित शिकायत की गई। जिस पर कोई कार्यवाही की गई। लड़की के पिता ने इस मामले में स्कूल से सूचना अधिकार के आवेदन के माध्यम से जानकारी मांगी गई। पहले तो स्कूल प्रशासन जानकारी देने में ना-नुकुर करता रहा और अपनी गलती के लिए लड़की के पिता से मौखिक माफी मांगकर मामला

रफा-दफा करना पड़ा। लेकिन गूंज द्वारा मामला उठाने के बाद संस्था द्वारा जानकारी दी गई।

सूचना अधिकार में हुआ बड़ा खुलासा, कमजोर बच्चों को योजनाबद्ध तरीके से किया गया प्राइवेट

स्कूल की 12 वीं की पूर्व छात्रा के पिता महेश सिंगार ने सूचना अधिकार में जानकारी मांगी थी। जिससे पता लगा कि, शा.क.उ.मा.वि. बामनिया के प्राचार्य द्वारा वर्ष 2022-23 के 12 वीं की कुल 24 छात्राओं को प्राइवेट किया गया। जिससे से मात्र 2 छात्राएं पास हुईं, जबकि 3 को पूरक और 19 छात्राएं फेल हो गईं। परिणाम से साफ होता है कि, संस्था द्वारा उन छात्राओं को ही कम उपस्थिति के नाम पर प्राइवेट किया गया जो पढ़ने में कमजोर थीं। सूचना अधिकार की जानकारी में सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ कि संस्था द्वारा कम उपस्थिति वाली छात्राओं के परिजनों को

विधिवत एक भी सूचना पत्र नहीं भेजा गया। संस्था ने लिखित जानकारी देते हुए बताया कि, कम उपस्थित छात्राओं को ही संस्था में जानकारी दी गई कोई सूचना पत्र छात्राओं के पालकों को नहीं दिया गया।

रिजल्ट नहीं बिगड़े इसलिए किया जाता है फर्जीवाड़ा, जांच हो तो हर बड़ी संस्था का होगा खुलासा

जिले की दसवीं और 12वीं के परिणाम लगातार गिरता जा रहा है। सरकारी स्कूल अपने वार्षिक परिणाम सुधारने के लिए कमजोर छात्र-छात्राओं को कम उपस्थिति के नाम पर प्राइवेट किया जाता है, क्योंकि प्राइवेट हुए बच्चों के परिणाम स्कूल के वार्षिक परिणाम

प्राइवेट हुई छात्राओं के परिणाम।

में नहीं जोड़ा जाता है। ये स्थिति सिर्फ बामनिया स्कूल की नहीं बल्कि विकास खण्ड सहित जिले भर की सरकारी संस्थाओं में खेल चल रहा है। फिलहाल इस मामले में महेश सिंगार की शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

स्कूल प्रशासन ने लिखित में नहीं दी परिजनों को कोई लिखित सूचना।

राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी 3 री के पाठ्यक्रम में छोटे से गाँव के शिक्षक का रहा विशेष योगदान सरकार के अंकुर अभियान की तरह पुस्तक का किया गया निर्माण

माही की गूंज, सारंगी।

कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। अगर आप मे काबिलियत है तो आपको उचित स्थान पर पहचान मिलेगी, ऐसा ही कुछ कर दिखाया पं. ट. ल. व. विकास खण्ड में स्थित छोटे से गाँव सारंगी में पदस्थ माध्यमिक शिक्षक पंकज

कुमार वैरागी (राज्य स्त्रोत विशेषज्ञ) ने। जिन्होंने सहयोगियों द्वारा मध्य प्रदेश के लगभग 59 हजार शासकीय प्राथमिक स्कूलों की कक्षा 3 के लिए इस सत्र में पढ़ाई जाने वाली अंकुर अभ्यास पुस्तिका एवं अंकुर टीचर गाइड का निर्माण किया है। गौरतलब है कि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण दस्तावेज निपुण भारत में वर्णित बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान (एफएलएन) के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मिशन अंकुर का शुभारंभ किया गया। मिशन के लक्ष्य को पाने के लिए कक्षा 1,2 तथा कक्षा 3 हेतु पाठ्यपुस्तक के अलावा अभ्यास पुस्तिका तथा टीचर गाइड का निर्माण किया गया है। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा पूरे मध्यप्रदेश के सभी प्राथमिक शिक्षकों को इसका प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण पुस्तिका का निर्माण भी शिक्षक वैरागी द्वारा किया गया है। शिक्षक वैरागी पूर्व में जिला स्तरीय, सभाग स्तरीय एवं राज्य स्तरीय प्रशिक्षण में हजारों शिक्षकों को प्रशिक्षित कर चुके हैं। शिक्षक वैरागी अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजन, माता-पिता, स्टॉफ साथियों के साथ-साथ विभागीय अधिकारियों को देते हैं जिन्होंने समय-समय पर अवसर उपलब्ध कराए।



सीएम राईस स्कूल मेघनगर का कलेक्टर ने किया निरीक्षण

माही की गूंज, मेघनगर।

नगर में जिले की कलेक्टर तन्वी हुड्डा द्वारा सीएम राईस शासकीय विद्यालय का निरीक्षण किया गया। कलेक्टर द्वारा बच्चों से मौसम के दौरान बोई जाने वाली फसलों के पर्यायवाची शब्द और पढ़ाई के बारे में प्रश्न पूछे गए और बच्चों से अंग्रेजी में पुस्तक से वाचन करवाया गया और अंग्रेजी शब्दों की बारीक जानकारी बताई गई।

कलेक्टर द्वारा स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों को समय पर कक्षा में

उपस्थित होने को लेकर बच्चों को अच्छी शिक्षा देने को कहा। वहीं शिक्षक द्वारा कक्षा में उपस्थित नहीं होने पर सतीश पाटीदार का 1 दिन का वेतन काट दिया गया। मेघनगर शासकीय स्कूल के प्राचार्य और शिक्षकों को स्कूल में आने वाले बच्चों को समय पर किताबें बांटने को वितरण करने को कहा। शासकीय स्कूल में शिक्षकों को अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ाने को कहा गया ताकि शासकीय स्कूल में आने वाले बच्चे अच्छे से अच्छे शिक्षा ग्रहण कर सकें और स्कूल में



आने वाले छोटे बच्चों को भी पढ़ाई में विशेष ध्यान रखें इस दौरान डिप्टी कलेक्टर मुकेश सोनी तहसीलदार सोनू गोयल नायाब तहसीलदार परवीन बानु बोईओ एवं सभी अधिकारी मौजूद रहे।

लाखों रुपए के नवीन भवन के गुणवत्ता की खुली पोल

माही की गूंज, जामली।

पहले ही बारिश में नवीन भवन की गुणवत्ता की पोल खुलती दिखाई दे रही है। यह मामला है ग्राम जामली के शासकीय हाई स्कूल का जहां पर ठेकेदार द्वारा बनाए जा रहे 3 से 4 वर्ष होने को है, भवन का अभी भी स्कूल प्रशासन को हँड ओवर नहीं हो पाया। जिसकी वजह से बारिश के दिनों में जगह-जगह जलभराव देखने को मिल रहा है। बारिश की शुरुआत में ही अभी से ही यह हाल है, तो आने वाले समय में क्या होगा ठेकेदार द्वारा किस तरह की गुणवत्ता का काम किया गया, यह देखने के लायक है। भवन में क्या-क्या कमियां हैं जिसको लेकर प्राचार्य मुकेश पाटीदार अपने सभी शिक्षकों द्वारा तीन से चार दिन पहले अवलोकन किया गया। जहां पर विभिन्न कमियां देखने को मिली उसको पश्चात प्राचार्य पाटीदार द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत कराने के लिए एक लेटर भी बनाया



गया जो जिला शिक्षा अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। जिसमें कई तरह की कमियां सामने आ रही हैं, जैसे मेन गेट पर बच्चों के प्रवेश के लिए जो पेडिया बनाई गई है वह उंची ज्यादा है व एक पेडी केवल 3 फीट की ही है। आसपास फर्श में गड्ढा रहने से पानी भरा रहता है, पानी का निकासी क्लान सही नहीं है कमरों में लाइट फिटिंग में

बटन की जगह खाली रहने से पूर्णता बंद करना आवश्यक है, ताकि कोई अनहोनी घटना नहीं हो। लैट बाथ के कमरों में फर्श सफाई नहीं, पानी की नलियां ओपन होने से टूट-फूट का खतरा बना रहेगा। नलियों की स्लिप से दीवार पर फिटिंग करवाना आवश्यक है एवं छत पर पानी भरा होना। दूसरा दीवारों में अभी सही पुड्री का तड़क जाना और प्लास्टर निकालना और कई जगह ऐसी है जहां पर छत पर सीलन आना शुरू हो गई है। अभ्यास कक्षा में ब्लैक बोर्ड का निर्माण नहीं किया गया, अब यह देखने वाली बात है कि, अधिकारी इसको लेकर कितने जिम्मेदार है और किस तरह की कार्रवाई करते हैं या फिर ठेकेदार और अधिकारी से मिलकर सांठ-गांठ कर मामले को रफा-दफा कर दें।

आज से बहेगी धर्म की गंगा

माही की गूंज, पेटलावद।



आज से मां अहिल्या की पावन नगरी पेटलावद में बहेगी की धर्म की गंगा। श्री सोमनाथ शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है कथा का समापन 19 जुलाई को होगा। प्रतिदिन बामनिया रोड स्थित स्थानीय सुंदर गार्डन पर दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक कथा का आयोजन होगा। खास बात यह है कि, कथा का वाचन

करने मालवा माटी में मां शारदा के वरद पुत्र पंडित श्री मनमोहन कश्यप (अग्निहोत्री) यहां आ रहे हैं। जिनके श्रीमुख से 7 दिनों तक धर्म की गंगा बहेगी। कथा की शुरुवात में भव्य कलश यात्रा आज 13 जुलाई को सुबह 8 बजे निलकण्ठेश्वर महादेव मंदिर से निकलेगी जो नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरेगी। नगर भ्रमण के बाद कलश यात्रा सुंदर गार्डन पहुंचेगी। जहां विधि विधान से पूजा पाठ के बाद शिव

महापुराण कथा प्रारंभ होगी। शिव महापुराण कथा की तैयारियां आयोजन समिति जोर शोरो से की गई। आयोजन में सबसे अहम भूमिका महिला मंडल निभा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार से भूतेश्वर महादेव फूट मंदिर से महिला मंडल ने पीले चावल रख आमंत्रण देने की मुहिम शुरू की थी महिला मंडल ने चरों घर पैदल भ्रमण कर पीले चावल रखकर कथा में आने का आमंत्रण दिया।

छात्र संगठन व्यवस्थाओ से नाराज, आये दिन महाविद्यालय की होती है तालाबंदी

माही की गूंज, पेटलावद।

एक बार फिर महाविद्यालय के छात्र-छात्राएं ने कॉलेज प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए महाविद्यालय की तालाबंदी कर दी। महाविद्यालय के छात्र अत्यवस्थाओ से लगातार परेशान हैं जिनका कोई निराकरण आज तक नहीं हो पाया है। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा समय-समय पर विद्यार्थियों की समस्या हेतु आप उच्चशिक्षा विभाग को समय-समय पर अवगत कराता आया है। किन्तु अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा 1 माह के भीतर शासकीय महावीर

महाविद्यालय पेटलावद में जो ज्ञान दिये उसका कोई परिणाम नहीं आया। वर्ष 2021-22 के विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष में एक ही विषय में पूरक दे दी गई, पूरक परीक्षा देने के बाद भी परीक्षा परिणाम में सुधार नहीं हुआ और जो अंक पूर्व में दिये थे वही अंक वापिस अंकसूची में दर्शा दिये गये। जबकि हमारे द्वारा संबंधित विषय की परीक्षा देने पर भी संबंधित विषय के अंकों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसके पश्चात् दूसरी बार पुनः परीक्षा देने के बाद भी वहीं पुनः अंक जो प्रथम वर्ष में दिये थे वापिस अंकसूची में दर्शा दिये गये जिससे हमारा परीक्षा परिणाम आज

दिनांक तक जारी नहीं हुआ। संगठन की मांग है कि, विद्यार्थियों द्वारा 2 बार परीक्षा देने के बावजूद भी परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होने से हम द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पायेगे एवं परीक्षा से वंचित रह जायेंगे और हमारे पूरे 2 वर्ष बर्बाद हो जायेंगे। महाविद्यालय प्रशासन द्वारा हम विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक ही विषय के अंकों को बार-बार विध्विद्यालय भेज देते हैं, विद्यार्थियों को भविष्य जाते हैं तो विध्विद्यालय महाविद्यालय से अंकों के प्राप्त नहीं होने का बोल देते हैं, महाविद्यालय आते है तो महाविद्यालय

विध्विद्यालय का बोल कर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, इस कारण से हम गरीब ग्रामीण विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। महोदय, विद्यार्थी दूर ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, किन्तु महाविद्यालय के प्राचार्य हम विद्यार्थियों को परेशान कर रहे हैं और सुनवाई नहीं करते हैं, और अधिकार रूप से अवकाश पर रहते हैं, महाविद्यालय में कोई भी उचित जवाब नहीं देता है। विद्यार्थी परिषद अंतिम चेतावनी देती है कि, एक सप्ताह में यदि परीक्षा परिणाम में सुधार नहीं किया जाता है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उा आन्दोलन करेगा।



आखिर फिर लगा प्राइवेट संस्था का बोर्ड इस बार बदल कर लगाया गया



माही की गूंज, पेटलावद।

नगर में कई सरकारी भवनों और सार्वजनिक स्थानों पर निजी संस्थाओं द्वारा बोर्ड लगाने का मामला सामने आने के बाद नगर में इन संस्थाओं के प्रयासों का विरोध हो रहा है। नगर के श्रद्धांजलि चौक पर कुछ दिनों पूर्व संस्था के नाम के साथ यात्री प्रतिष्ठालय लिखा गया था जिसका विरोध शोसल मीडिया होने के बाद नगर परिषद की भारी किरकिरी हुई जिसके बाद नगर परिषद ने रातों रात बोर्ड उतरवा लिया। बोर्ड उतरने के बाद संस्था नगर के अन्य हिस्सों में दूसरी संस्थाओं के बोर्ड का हवाला देकर एक बार फिर बोर्ड सार्वजनिक शासकीय यात्री प्रतिष्ठालय पर बोर्ड में सुधार कर लगा दिया इस बार संस्था ने यात्री प्रतिष्ठालय का अपना बताने की जगह सौजन्य लिख कर लगाया। नगर में अब इस बात को लेकर चर्चा है कि क्या नगर परिषद नगर की शासकीय सार्वजनिक भवनों को रंगाई पुताई के नाम पर सरकारी संपत्ति का नामकरण मनमाने ढंग से किया जा सकता है।

विभाग और स्थानीय नेताओं की लापरवाही से हो रही सरकार की किरकिरी सरकार की ट्रांसफर नीति पर उठ रहे सवाल, क्या आंख बंद कर के प्रभारी मंत्री ठोक रहे अनुशांसा के हस्ताक्षर

पेटलावद विकासखंड में लापरवाही की हद, सेवानिवृत्त एक शिक्षक दो जगह तो बीएड के लिए रिलीव शिक्षक का भी कर दिया तबादला

माही की गूंज, पेटलावद। राकेश गोहलोत

विधानसभा 2023 के चुनाव आते-आते सरकार की हालात खराब होती जा रही। कहीं संगठन में हलचल तो कहीं आदिवासी और दलित पर अत्याचार तो भाजपा के प्रशासन के बड़े अधिकारी पर दर्ज मामला भाजपा के लिए मुसीबत बने हुए है। इन सब के बीच भाजपा की परेशानीया कम होने का नाम नहीं ले रही। वर्तमान में चल रही ट्रांसफर नीति के प्रशासन और स्थानीय नेताओं के कारण भाजपा की भारी किरकिरी हो रही है। 7 जुलाई को जारी ट्रांसफर सूची में रिटायर्ड शिक्षक का नाम आने पर भारी हल्ला हुआ। जिससे भी सरकार के नुमाइंदों ने सबक नहीं लिया और एक ही शिक्षक के दो जगह तबादले कर दिए गए। जबकि एक अन्य शिक्षक जो फिलहाल बीएड के लिए रिलीव है उसका भी स्तान्तरण कर दिया गया।

मामला नम्बर 1

रिटायर्ड शिक्षक का हुआ स्तान्तरण

ट्रांसफर के खेल में मध्यप्रदेश सरकार स्थानीय नेताओं और अधिकारियों की लापरवाही की वजह से घिरती नजर आ रही है। यहां 7 जुलाई को जारी स्थान्तरित शिक्षकों की सूची आते ही स्थानीय प्रशासन और नेता हसी के पात्र बन गए। जब सूची में लगभग छह माह पूर्व रिटायर्ड हो चुके शिक्षक सज्जनसिंह डामर को बामनीया से पिटोल कर दिया गया। शिक्षक का नाम स्तान्तरण की सूची में शामिल मिला। मामला जैसे ही रिटायर्ड शिक्षक के पुत्र ने सोशल मीडिया पर स्तान्तरण के आदेश की कॉपी के साथ रिटायर्ड पिता के स्तान्तरण के लिए भाजपा सरकार और भाजपा नेताओं को बधाई दी। इस स्टेटस के बाद सोशल मीडिया पर इस ट्रांसफर की लेकर भाजपा की जम की खिल्ली उड़ाने लगे।

मामला नम्बर 2

एक शिक्षक का दो जगह हुआ तबादला

पेटलावद विकासखंड के संकुल केंद्र मठमठ अंतर्गत शासकीय प्राथमिक विद्यालय में पदस्थ रमेश वसुनिया का दो अलग-अलग आदेश के तहत अलग-अलग विकासखंड में हुआ प्रशासनिक ट्रांसफर। विगत दिनों शिक्षकों के प्रशासनिक व स्वेच्छिक स्थान्तरण को लेकर जिले के प्रभारी मंत्री इंद्रसिंह परमार द्वारा भाजपा नेताओं द्वारा बनाई गई, स्थान्तरण सूची का अनन-फानन में अनुमोदन कर दिया। 7 जुलाई को अनुसूचित जनजाति कार्य विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 4551 में सरल क्रमांक 24 में अंकित रमेश वसुनिया का स्थान्तरण शासकीय प्राथमिक विद्यालय पोलाखण्ड से प्राथमिक विद्यालय सालेड़ा फुलिया दोतड कर दिया। वहीं विभाग द्वारा दूसरे आदेश क्रमांक 4557 में सरल क्रमांक 10 में अंकित रमेश वसुनिया का प्रशासनिक स्थान्तरण शा. प्राथमिक विद्यालय पोलाखण्ड से शासकीय प्राथमिक विद्यालय हमीरफुलिया हरिनगर विकास खण्ड थांदला में हुआ। अब शिक्षक रमेश वसुनिया असमंजस में कि, मैं किस स्कूल में जाऊँ करे और अधिकारी शिक्षक की किस संस्था के लिए रिलीव करे।

मामला नम्बर 3

स्वेच्छिक को प्रशासनिक बनाकर काटी जा रही चांदी, बीएड के लिए रिलीव शिक्षक का सीएम राइस खवासा के लिए हो चुका था चयन

सरकार ट्रांसफर नीति की आड़ में लेन-देन का खुला खेल चल रहा है। जिसका प्रमाण लगातार तबादला सूची में हो रही लापरवाही देखने में आ रही। पेटलावद विकास खण्ड में तीसरा मामला सामने आया है जहां शिक्षक शांतिलाल सिंगाड़ जो की हाई स्कूल झोसर में पदस्थ है उन्हे विभाग ने दो वर्ष के लिए बीएड करने के हेतु डाइट देवास के लिए रिलीव किया गया है और फिलहाल दूसरा वर्ष चल रहा है। इस बीच विशिष्ट विद्यालयों के लिए अयोजित विभागीय परीक्षा में उक्त शिक्षक सम्मिलित हुआ था और उनका चयन सीएम राइस थांदला किया गया था। संकुल प्राचार्य द्वारा शिक्षक का डाइट देवास में बीएड करने का हवाला देकर कार्य मुक करने से इन्कार कर दिया था। अब जादू देखिए कि, उक्त शिक्षक थांदला नहीं जाना चाहता था, तगड़ी सेटिंग के दम पर शांतिलाल सिंगाड़ का स्थानांतरण पुनः हाई स्कूल झोसर से उक्त विद्यालय पेटलावद हो गया है अब देखना है संकुल प्राचार्य की इसमें क्या भूमिका है शिक्षक को उसकी मनचाही स्थान पर ज्वाइनिंग देगे या उसका पुर्व के आदेश उक्त विद्यालय थांदला भेजेगे। कुल मिलाकर ट्रांसफर की चासनी ले रहे है जिसके लिए सरकार और प्रभारी मंत्री तक साख दांव पर लगा दी गई।



क्र.सं.	नाम	वर्ग	वर्ग संख्या	वर्ग संख्या का नाम
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

कार्यवाही होगी की लीपापोती

एक के बाद एक तीन मामले पेटलावद विकास खण्ड में सामने आए है। यही ट्रांसफर आदेशों को बारीकी से जांच की जाए तो पेटलावद विकास खण्ड सहित अन्य विकास खंडों में ऐसे मामले सामने आएंगे। क्या सरकार में बैठे जिम्मेदार नेता इस लापरवाही के लिए जबाबदार स्थानीय नेताओं और जिले के अधिकारियों पर कार्यवाही करेगे या सब इस खेल में शामिल है ये देखना दिलचस्प होगा।

क्र.सं.	नाम	वर्ग	वर्ग संख्या	वर्ग संख्या का नाम
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

क्र.सं.	नाम	वर्ग	वर्ग संख्या	वर्ग संख्या का नाम
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

आस्था और विश्वास की डोर थामें बाबा के भक्त, अमरनाथजी यात्रा को खाना

दो दिन से रुकी यात्रा जल्द बहाल होने का मोलें भक्तों को है विश्वास

मप्र व छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री ने किया भ्रमण

माही की गूंज, थांदला/झाबुआ।
पूरे भारत को एकता के सूत्र में बाँधने वाली विश्व प्रसिद्ध एक मात्र अमरनाथजी यात्रा को लेकर भोलें भक्तों में अपार उत्साह रहता है। जैसे ही अमरनाथ साइन बोर्ड द्वारा प्रारंभ होने की तिथि की घोषणा होती है वैसे ही उत्साहित भोलें भक्त यात्रा के लिए अपना स्थान सुरक्षित कर लेते हैं ऐसे में यात्रा में आने वाली बाधा भी उनके हौसलों को कम नहीं करती है।
वीगत दो दिनों से भारी बारिश व भू-स्खलन के चलते यात्रा रुकी हुई है, बावजूद इसके देश के तमाम हिस्सों से यात्रियों का जम्मू जाने का सिलसिला नहीं थम रहा है। झाबुआ जिले से भी करीब 50 से ज्यादा यात्रियों का जत्था जम्मू तब से खाना हुआ। जिसमें भोलें भण्डारा परिवार के सदस्य भी शामिल है। उनका विश्वास है कि, बाबा भोलें भक्तों की थोड़ी परीक्षा तो लेते ही है, उन्हें विश्वास है जल्द ही दोनों मार्ग से यात्रा



शुरू हो जाएगी व भोलें भक्त अपने बाबा के दर्शन कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि, भोलें भक्तों का विश्व के एक मात्र हिम शिबलिंग के दर्शनार्थ जाने के लिए महज जुलाई-अगस्त दो माह का ही समय रहता है, जो बालटाल व पहलगाम से दो मार्ग व पंचतरणी तक हवाई यात्रा से वे बाबा के दर्शन कर सकते है। इस दौरान यात्रियों की सेवा, सुरक्षा का जिम्मा देश की सरकार के जवान करते है, जिससे यह यात्रा धार्मिक यात्रा के साथ राष्ट्रीय एकता के रूप में भी जानी जाती है। ऐसी दुकर व कठिन यात्रा में सभी शामिल होने वाले भायशाली भोलें भक्तों के उत्साहवर्धन व

शुभकामनाएं देने के लिए जब जीवदया अभियान के राष्ट्रीय संयोजक पवन नाहर, गौ भक्त आत्माराम शर्मा, भोलें भक्त प्रकाशचंद्र सोनी, उदारमना तुलसी मेहता, रोटीरी क्लब अध्यक्ष चंदनबाला शर्मा, सुनील डावी, दशरथ कडु, रहीम शेरानी, भूपेंद्र बरमण्डलिया, चिन्

माही की गूंज, थांदला।
मप्र व छत्तीसगढ़ राज्य के भाजपा के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल सोमवार को थांदला पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने नपाध्यक्ष श्रीमति लक्ष्मी सुनील पण्डा के पीएम आवास योजना में बने घर पर पहुंचकर स्वल्पाहार किया। इस दौरान जिले के भाजपा पदाधिकारियों से संवाद कर जामवाल ने बृथ मजबूतीकरण को लेकर नेताओं को प्रेरित किया। भाजपा के जिलाध्यक्ष भानू भूरिया ने मंडल महामंत्री सुनील पण्डा के बारे में संगठन मंत्री को जानकारी दी और बताया कि, उनका यह आवास पीएम आवास योजना में



बनाया हुआ है। सुनील पण्डा के व्यक्तित्व के बारे में बताते हुए नायक ने कहा कि, वह 20-25 वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर समाजसेवा के कार्य करते रहे है। साथ ही थांदला की जनता को आवाज पर उनकी पत्नी को नगर परिषद अध्यक्ष बनाया गया है।
भाजपा द्वारा किए गए कार्यों को लेकर क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए अच्छे विकास कार्यों को करने के लिए शुभकामनाएं भी प्रेषित की। इस दौरान नपाध्यक्ष श्रीमति लक्ष्मी सुनील पण्डा ने तिलक लगाकर घर आए सभी अतिथियों का स्वागत किया।

अपने दायित्वों को नहीं निभा पा रही ग्राम पंचायत

माही की गूंज, खवासा।
ग्राम पंचायत खवासा द्वारा विगत मई और जून का जलकर न लेने का निर्णय लिया गया जिसको लेकर ग्राम में चर्चाओं का बाजार गर्म है। ग्राम पंचायत का यह निर्णय खुद की असफलता की स्वाकारोडक है इस निर्णय से ग्राम पंचायत ने यह साबित कर दिया है कि, वो गमी में ग्रामवासियों को पेयजल उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं और इस असमर्थता की स्थिति में सरकार को चाहिए कि, वो अन्य कोई वैकल्पिक निर्णय लें क्योंकि पेयजल और स्वच्छता का विषय स्थानीय प्रशासन का है और स्थानीय प्रशासन इसमें असमर्थ है तो वरिष्ठ कार्यालय को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए।
प्रदेश की सरकार में लगभग 20 वर्षों से काबीज भाजपा की सरकार के द्वारा भाजपा समर्थित ग्राम पंचायत के माध्यम से 20 वर्षों में भी खवासा (जो कि थांदला विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है) में पेयजल उपलब्ध न कर पाना स्थानीय पंचायत के साथ प्रदेश सरकार की भी बड़ी विफलता है। इसके लिए



प्रदेश के साथ ही जिला स्तरीय जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को आम जनता को जवाब देना चाहिए। न की कर माफी जैसे निर्णय लेने चाहिए। क्योंकि कर न लेना किसी समस्या का समाधान नहीं है, यही नहीं आम जनता तो टेक्स दे रही है और देना भी चाहती है लेकिन बदले में उन्हें आधारभूत सुविधाएं चाहिए और वो आधारभूत सुविधाएं ग्राम पंचायत देने में विफल रही।
जनप्रतिनिधि की शपथ का भी उल्लंघन
निर्वाचित जनप्रतिनिधि द्वारा जनता की सेवा करने की शपथ ली जाती है। संविधान द्वारा प्रदान किये की रक्षा करने का दायित्व भी शासन और प्रशासन का रहता है और मूलभूत सुविधा उपलब्ध करने का दायित्व

अगर अपने कार्यों में लापरवाही बरतता है तो उस पर निलंबन और बर्खास्तगी जैसी कार्यवाही की जाती है लेकिन अगर जनप्रतिनिधि अपने कार्यों में लापरवाही करता है तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं ऐसा दोहरा मापदंड क्यों...?
आखिर कब होगा

खवासा की जल समस्या का हल
गत वर्ष चुनाव के समय चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों ने जनता से बड़े-बड़े वादे किए थे माही और नर्मदा तक का जल लाने के सपने दिखाए गए थे लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी समस्या में कमी नहीं बल्कि वृद्धि ही हुई है। यही नहीं ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में जनप्रतिनिधियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से धरने प्रदर्शन की चेतावनी भी दी

थी लेकिन न धरना प्रदर्शन हुआ और न ही जल समस्या का कोई समाधान। जुलाई माह के द्वितीय सप्ताह में भी आम जनता को जल समस्या का समाधान नहीं मिला है और अभी भी निजी टैंकरों के हवाले खवासा की पेयजल आपूर्ति हो रही है।
अनुपातिक जल कर लें
मई और जून में पेयजल वितरण न होने के कारण जलकर वसूली स्थगित की गई है लेकिन खवासा में तो बारहमासी जल संकट रहता है। पंचायत जलकर मासिक लेती है जबकि आम दिनों में भी खवासा में 8 से 10 दिन में एक बार जल वितरण होता है। अगर मई-जून के माफ करें तो अन्य माह में भी अनुपातिक पैसे ही लिए जाना चाहिए। महीने में तीन से चार बार जल वितरण होता है और पैसे पूरे महीने के मान से लिए जाते हैं। ऐसे में पंचायत को अन्य माह में कितने दिन पेयजल वितरण हो उतने ही दिन के पैसे ले जाना चाहिए। यही नहीं अन्य किसी कार्य को भी अगर पंचायत नहीं कर पाती है तो उसका हर्जाना भी पंचायत को चुकाना चाहिए।

भगवान भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार

माही की गूंज, थांदला।
श्रावण के प्रथम सोमवार पर अल सुबह से देर शाम तक शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। प्रातः जलाभिषेक करने हेतु बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सायं के समय भी दर्शन हेतु बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिवालयों में पहुंचे। नगर के श्री बड़ा गणेश मंदिर, श्री तेजाजी मंदिर, घोड़कुंड महादेव मंदिर रामेश्वर महादेव मंदिर शहीद नगर के विभिन्न शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ का विभिन्न तरीकों से आकर्षक श्रृंगार किया गया। संस्था के समय महाआरती का भी आयोजन किया गया। नगर के श्री रामेश्वर महादेव मंदिर पर बालक चेतन मेहते ने जुट एवं रस्सियों का बेहतरीन उपयोग करते हुए भगवान भोलेनाथ का आकर्षक स्वरूप तैयार किया। जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे व दर्शन लाभ लिया।



संपादकीय

बारिश से तबाही



उत्तर भारत समेत देश के अन्य भागों में अप्रत्याशित रूप से लगातार होती बारिश ने हा-हाकार मचाया है। बरसात के मौसम में बारिश और जलधाराओं में उफान आना सामान्य बात है। लेकिन इस बार की अतिवृष्टि ने बताया है कि मनुष्य शक्तिशाली होने का भले ही दंभ भरता रहे लेकिन कुदरत के रोद के सामने वह बीना ही है। जगह-जगह बाढ़ल फटने, नदियों में बाढ़, पानी रोकने में नाकाम बांध और भूस्खलन की घटनाओं ने लोगों में भय पैदा किया है। देश का जनजीवन अस्त-व्यस्त हुआ है। पुलों के टूटने, बस्तियों में नौका चलाने, मकानों के भरभरा कर गिरने व कारों के बहने के वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को दृश्यात से भर रहे हैं। कारोबार टप है, स्कूल-कॉलेज बंद कर दिये गये हैं। फिर भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। कई राज्यों में रेड, ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश ने कोहराम मचाया है। करीब तीन-चार हजार करोड़ रुपये का नुकसान होने का प्राथमिक अनुमान लगाया गया है। हिमाचल में बाढ़, बाढ़ल फटने, जलधाराओं में उफान व भूस्खलन में सत्रह लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं। जलधाराओं में उफान से नदियों के किनारे स्थित सड़कों, मकानों, होटलों व हाईवे को नुकसान पहुंचना स्वाभाविक है। हिमाचल व उत्तराखंड में सैकड़ों सड़कों तबाह हुई हैं। विद्युत व्यवस्था टप होने और यातायात बाधित होने की भी खबरें हैं। हिमाचल में रावी, व्यास, सतलुज, चिनाब आदि नदियों में उफान से संकट गहरा हो रहा है। हरियाणा में हथनीकुंड बैराज में जरूरत से ज्यादा पानी जमा होने से करीब दो लाख क्यूबिक पानी छोड़े जाने से दिल्ली पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में युद्ध स्तर पर बचाव के प्रयास किये जाने की जरूरत है। अभी भी रुक-रुक कर होने वाली बारिश को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में हालात चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। निःसंदेह, आज पूरी दुनिया में मौसम के दरम से उत्पन्न प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। मौसम की तल्खी को देखकर लगता है कि प्रकृति के खिलाफ मानव की क्रूरता का कुदरत बदला ले रही है। जलधाराओं के मार्ग में लगातार बढ़ते अतिक्रमण ने नदियों के प्रवाह को आक्रामक बना दिया है। पहाड़ हमारी जरूरत हैं, हमारी प्राणवायु के संरक्षक हैं लेकिन वे रिफ्ट इसानी विलासिता और सैर-सपाटे के स्थान नहीं हैं। वे बड़ी विकास परियोजना व बड़े बांधों का बोझ उठाने लायक भी नहीं हैं। कहा जाता है कि बड़े बांधों के इलाकों में बाढ़ल फटने की घटनाएं बढ़ती हैं। इंसान ने विकास व पर्यटन तथा बस्तियों का जितना बोझ पहाड़ों पर लाद दिया है, वो इनकी क्षमता से अधिक है। पहाड़ों में विकास का आधार प्रकृति के साथ सामंजस्य होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर देश के महानगर व शहर अनियोजित विकास का त्रास झेल रहे हैं। थोड़ी सी बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। बारिश के पानी को परंपरागत रास्ते थे, उन पर कब्जा करके हमने कंक्रीट के जंगल उगा दिये हैं। दूसरी ओर इस तरह की अतिवृष्टि आधारभूत ढांचे की पोल भी खोलती है। बड़े शहरों में सड़कों में जलमग्न, रेतवें लाइन का पानी में डूबना व अंडरपास का जलमग्न होना अनियोजित विकास का ही परिणाम है। बारिश में हमारे आधारभूत ढांचे की गुणवत्ता सामने आ जाती है। जिसके चलते सड़कों के धंसने और ट्रैफिक जाम की घटनाएं बारिश में सामने आती हैं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जिस मानव का हम पलक-पांवड़े बिछा कर स्वागत करते थे, जो बारिश कभी आनंद का प्रतीक होती थी, वह अब डराने वयों लगी है। कहीं न कहीं हमारे नगर नियोजक, प्रशासक, इंजीनियर व नीति निर्यात भविष्य की चुनौतियों के महेनजर विकास योजनाओं को मूर्त रूप देने में विफल रहे हैं। जाहिर बात है, यदि आधारभूत ढांचे का मिनिमम पर्याप्त योजना व दूरदर्शी सोच के अभाव में किया जाएगा, तो अतिवृष्टि से लोगों का मुश्किलों में फंसना स्वाभाविक ही है।

हिमालयी अस्मिता बचाने से रूकेंगी आपदाएं

दस वर्ष बाद अतिवृष्टि फिर कहर ढा रही है। जहाँ 2013 में उत्तराखंड तबाह हुआ था, वहीं 2023 में हिमाचल। मंडी शहर तो जल प्लान के कगार पर है। सिरमौर में लोग फंसे हुए हैं। अटल टनल बंद है और शिमला-मनाली हाईवे के यात्री इधर-उधर टिके हैं। व्यास नदी उफान पर है। उत्तराखंड में भी दस साल पहले जैसी विपदा भले न आई हो लेकिन पूरा राज्य बाढ़ की चपेट में है। पंजाब, हरियाणा के साथ-साथ दिल्ली-एनसीआर भी बदहाल है। वैसे जल-भरव और बाढ़ की हालत इन राज्यों के लिए आम हो गई है। मगर पिछले कुछ वर्षों से राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के सूखे इलाकों में भी पानी भर रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर विचार न किया गया तो भविष्य में स्थिति और भयावह हो जाएगी।

बहुत से लोग वह भयावह मंजर भूल चुके होंगे जब 2013 में केदारनाथ हादसा हुआ था। उस समय 16 जून की रात अचानक केदारनाथ में जोर का धमाका हुआ और नीरव सरोवर में पानी की ऊंची-ऊंची लहरों ने पत्थरों को लुढ़काना शुरू कर दिया। गर्मी के दिन थे इसलिए उत्तराखंड के इस प्राचीन शिव मंदिर के दर्शनों के लिए असंख्य श्रद्धालु आए हुए थे। इस हादसे में कितने लोग मारे गये और कितने लापता हुए, इसका कोई पुख्ता आंकड़ा आज तक नहीं मिल सका है।

बस यही बताया गया कि केदारनाथ धाम के चोराबारी ग्लेशियर के ऊपर बाढ़ल फटा था। इसके बाद जो भगदड़ मची उसमें कौन कहां गया, कुछ नहीं पता चल सका। केदारनाथ के एक तरफ 22,000 फीट ऊंची केदारनाथ पहाड़ी है दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंची करारकुंड और तीसरी तरफ 22,700 फीट ऊंचा भरतकुंड है। इन तीन पर्वतों से होकर बहने वाली पांच नदियां हैकुमदाकिनी, मधुगंगा, चिरगंगा, सरस्वती और स्वर्दरी। उस रात ये सारी नदियां उफान पड़ी थीं। इसके बाद पूरे उत्तराखंड में ज्वरदस्त बारिश शुरू हो गई और यह पहाड़ी राज्य बुरी तरह बाढ़ से चिर गया। हादसे से उत्तराखंड के बाकी धाम (बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री) भी सैलाब से बच नहीं सके। बाद में उत्तराखंड की बदहाली को जितना आँसू, वे दिल दहला देने वाले थे। पानी के सैलाब ने सब कुछ लील लिया था। केदारनाथ में तो सिर्फ केदारनाथ का मंदिर ही शेष बचा था। कल्पुरी शैली में बने इस मंदिर की बनावट ऐसी है कि इसका

ध्वंस लगभग असंभव है। देहरादून के वाडिया इंस्टिट्यूट की मानें तो 13वीं सदी से 17वीं सदी तक यह मंदिर बर्फ से दबा रहा। लेकिन जब बर्फ हटी तो मंदिर यथावत था।

दरअसल, कल्पुरी शैली में बने मंदिरों को इस तरह बनाया गया था कि वे प्राकृतिक आपदाओं में सुरक्षित रह सकें। किंतु मनुष्य जो आपदाएं लाते हैं, उनसे प्रकृति कुपित होती है। प्रकृति के कुपित होने से सबसे अधिक नुकसान मनुष्यों को ही होता है। मगर मनुष्य उसे कुपित करने के सारे उपक्रम करते रहते हैं। उस समय लगा था कि शायद मनुष्य इस हादसे से चेतना और नदियों के जल प्रवाह को रोकने या बाधित करने की हरकतें नहीं करेगा। मगर उस हादसे को लोग भूल गये, और फिर से वैसे ही हरकतें शुरू कर दीं, जो प्राकृतिक कोप का कारण बनती हैं। जैसे नदियों के जल-प्रवाह को रोकना, उसके प्रसार क्षेत्र में खनन, डूब क्षेत्र में बसावट। नतीजा यह होता है कि न बाढ़ रुक पाती है न सूखा।

दरअसल, प्रकृति के कोप से बचने के जो उपाय तलाशें गये थे, उनकी अवहेलना समाज को भारी पड़ती है। केदारनाथ की सभी नदियों के प्रवाह क्षेत्र में यदि होटल और गेस्ट हाउस न बनाये जाते तो यकीन चोराबारी ग्लेशियर से आया पानी अपनी स्वाभाविक गति से बह जाता। किंतु जिस तरह से बर्फ भीड़ को ठहराने के लिए मंदकिनी के बहाव को बाधित किया गया, उससे यह बर्बादी होनी ही थी। पहले तीर्थयात्री केदार धाम में अपनी आस्था और श्रद्धा के चलते आता था। मगर पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से उसे एक धार्मिक स्थल से पर्यटन स्थल बना दिया गया। नतीजा लोग सिर्फ मौज-मस्ती के लिए यहाँ आने लगे।

करीब एक हजार साल से भी ज्यादा समय तक केदारनाथ मंदिर अपनी भयव्यता और दुर्गमता के कारण

जाना जाता रहा है। बद्री और केदार घाटी की खोज आदि शंकराचार्य ने की थी। तब यहाँ तिब्बती बौद्धों का कब्जा था लेकिन आदि शंकराचार्य का कहना था कि भगवान नारायण ने यहाँ साक्षात् अवतार लिया था और बाद में बौद्धों ने उनकी प्रतिमा कुंड में फेंक कर इस घाटी पर कब्जा कर लिया। आदि शंकराचार्य अपने साथ कुछ दक्षिणात्य ब्राह्मणों को लेकर गए थे और भयानक शीत में वे कुंड में कूदे तथा भगवान बद्री की प्रतिमा निकाली तथा उसे स्थापित किया। उनके बाद कल्पुरी राजाओं के शिल्पी आए तथा उनकी रक्षा के लिए सेना भी। शिल्पियों ने यहाँ के पत्थरों से बद्री और केदार घाटी में क्रमशः भगवान बद्रीनाथ तथा शिवलिंग की भव्य मूर्तियां स्थापित कीं। शंकराचार्य ने आज से हजार साल पहले भारत देश को एक सूत्र में पिरोने की एक ऐसी अवधारणा प्रस्तुत की जो शायद उसके पहले किसी ने नहीं सोची थी।

पूरे भारत के पश्चिमोत्तर से लेकर पूर्वोत्तर तक हिमालय ही फैला है। और इसके नीचे का भूभाग एक प्रायद्वीप जैसा है जिसका सारा मौसम हिमालय की पहाड़ियों और बर्फ से ढकी चोटियों से प्रभावित होता है। आज अगर भारत का मौसम उष्ण कटिबंधीय है तो उसकी वजह यही हिमालय है। जाड़ा, गर्मी और बरसात की वजह यही हिम प्रदेश है। वनां शायद भारत में ही अन्य मुल्कों की तरह एक-सा मौसम रहा करता। या तो भयानक गर्मी या भयानक जाड़ा अथवा बारहों महिने की बारिश। पर हिमालय में शहर बसाने की कल्पना करने वाले हमारे हुक्मरान भूल जाते हैं कि हिमालय दुनिया का सबसे नया पहाड़ है। इसे आल्पस की तरह तोड़ा नहीं जा सकता है न ही इसे अरावली की तरह रौंदा जा सकता है। इसीलिए हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसे धर्म और अध्यात्म का केंद्र बताया गया है। चाहे वे वैदिक ऋषि-मुनि रहे हों अथवा बौद्ध व सिख, वे हिमालय में अपने अध्यात्म की

भूख मिटाने गए। इसीलिए सदैव से हिमालय में तीर्थयात्री जाते रहे हैं, पर्यटक नहीं। पर्यटकों के लिए अग्रियों ने अपेक्षाकृत कम ऊंची पहाड़ियों को विकसित कर लिया था। शिमला, कसौली, मसुरी, नैनीताल से लेकर दार्जिलिंग तक। इसके ऊपर का भाग सिर्फ धार्मिक यात्रियों तक सीमित रखा गया और अभी गुल पचास साल पहले तक ये धार्मिक यात्री बद्री, केदार, गंगोत्री तथा यमुनोत्री की पूरी यात्रा हरिद्वार से ही पैदल तय करते थे। पहले जो भी यात्री इन धामों की यात्रा करने जाया करते थे वे अपने नाते-रिस्तेदारों से मिलकर यात्रा शुरू करते थे क्योंकि उनके सुरक्षा लौटने की उम्मीद कम ही हुआ करती थी। एक कहलवत प्रचलित थी- जाए जो बद्री, वो लौटे न उड़ी, और लौटे जो उड़ी तो होय न दलितरी। यानी बद्री-केदार जाने वाले का लौटना यदकदा ही हो पाता था और लौटा तो फिर वह गरीब तो नहीं रहता था।

गोमुख तक आज यात्रियों की भीड़ में आध्यात्मिकता कम इन इलाकों में जाकर मौज-मस्ती करने का भाव अधिक रहता है। इसीलिए वे अपने साथ खाने-पीने की इतनी चीजें ले जाते हैं कि उनकी गंदगी से इस सारे क्षेत्र से पानी निकलने के रास्ते तक बंद हो गए हैं। पहले के यात्री सौधों में जाकर मौज-मस्ती करने का भाव हिमालय का जुगाड़कर चूल्हा जलाया और खिचड़ी बनाकर खा ली लेकिन अब तो उन्हें वह सब चाहिए जो दिल्ली आदि महानगरों में उपलब्ध है। उनकी चाहत के लिए यहां दुकानें तथा होटल खुले। अधिकतर होटल नदी द्वारा छोड़ी गई रेतों में बनाए गए और सारा कचरा नदी में फेंका जाने लगा। नतीजा यह हुआ कि नदी में गंद जाम होकर धारा प्रभावित होने लगी। जो जगह वापरप्रस्थ में प्रवेश कर चुके यात्रियों के लिए तय की गई थी उसमें वह लोग भी अपना हक जमाने लगे जिन्होंने अभी जिनगी शुरू तक नहीं की है। मानवीय हस्तक्षेप ने हिमालय की सूरत बिगाड़ दी है। अब अमर सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून हिमालय की चोटियों से टकरा कर नमी पैदा करता है। नतीजा होता है, घनघोर बारिश।



जयंतीलाल भंडारी

जीवन के लिए नयी संभावनाओं की तलाश

रोवर में 'प्रज्ञान' वेहद महत्वपूर्ण है। यही प्रज्ञान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के बाद अपने काम में जुट जाएगा। यहाँ की सतह में पानी और खनिजों की खोज करेगा। चंद्रमा पर हेलियम की खोज करके उससे पृथ्वी पर फ्यूजन पद्धति से ऊर्जा की समस्या का हल करने की परिकल्पना वैज्ञानिकों के दिमाग में है। दरअसल फिलहाल चंद्रमा पर गहरा अंधेरा व सन्नता प्रचलित है। अतएव कृत्रिम तरीकों से बिजली पैदा की जाएगी। यहाँ जीवनदायी तत्व हवा, पानी और अमिन नहीं है। ये तत्व नहीं हैं इसलिए, जीवन भी नहीं है।

याद रहे भारत द्वारा 2008 में भेजे गए चंद्रयान-1 ने ही दुनिया में पहली बार चंद्रमा पर पानी होने की खोज की थी। चंद्रयान-2 की असफलता का विस्तार चंद्रयान-3 है। यह अभियान मानव को चांद पर उतारने जैसा ही चमत्कारिक होगा। इस अभियान की लागत करीब 7,000 करोड़ रुपये आ जाएगी। चांद पर उतरने वाला यान अब तक चंद्रमा के अछूते हिस्से दक्षिणी ध्रुव के रहस्यों को खंगालेगा। चंद्रयान-3 इसरो का पहला ऐसा मिशन है, जो



किसी दूसरे ग्रह की जमीन पर अपना यान उतारोगे। दक्षिणी ध्रुव पर यान को भेजने का उद्देश्य इसलिए अहम है, क्योंकि यह स्थल दुनिया के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए अब तक रहस्यमय बना हुआ है। यहाँ की चट्टानें 10 लाख साल से भी ज्यादा पुरानी बताई गई हैं। इतनी प्राचीन चट्टानों के अध्ययन से ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति को समझने में मदद मिल सकती है। इससे इतर इस पर लक्ष्य साधने का अन्य उद्देश्य चंद्रमा के इस क्षेत्र का अब तक अज्ञात रहना भी है। दक्षिणी ध्रुव पर अब तक कोई भी यान नहीं उतारा गया है। अब तक के अभियानों में ज्यादातर यान चंद्रमा की भूमध्य रेखा के आसपास ही उतरते रहे हैं। चांद पर उतरने की दिलचस्पी इसलिए भी है, क्योंकि यहाँ एक तो पानी उपलब्ध होने की संभावना जुड़ गई है, दूसरे यहाँ ऊर्जा उत्सर्जन की संभावनाओं को भी तलाशा जा रहा है।

पर जाकर ध्वस्त हो जाता है, या फिर अंतरिक्ष में कहीं भटक जाता है। इसे न तो खोजा जा सकता है और न ही निगरात करके दोबारा लक्ष्य पर लाया जा सकता है। दरअसल, 7 सितंबर, 2019 की रात्रि में 1:40 बजे भारत ने चंद्रयान-2 भेजा था। लेकिन रात्रि 2:50 बजे अभियान पर पानी फिर गया।

वर्ष 1960 के दशक में जब अमेरिका ने उपग्रह भेजे थे, तब उसके शुरू के छह प्रक्षेपण के प्रयास असफल रहे थे। अविभाजित सांविध्य संघ ने 1959 से 1976 के बीच 29 अभियानों को अंजाम दिया। इनमें से 17 असफल रहे थे। 1959 में रूस ने पहला उपग्रह भेजकर इस प्रतिस्पर्धा को गति दे दी थी। तब से लेकर अब तक 67 चंद्र-अभियान हो चुके हैं, लेकिन चंद्रमा के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं जुटाई जा सकी है। इस तरह का ही नतीजा रहा कि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कनेडी ने चंद्रमा पर मानव भेजने का संकल्प ले लिया। 20 जुलाई, 1969 को अमेरिका के वह ऐतिहासिक उपलब्धि वैज्ञानिक नील आर्मस्ट्रॉंग और बज एल्ड्रिन और चंद्रमा पर उतराकर प्राप्त भी कर ली। इसी से कस्मताल मिलते हुए रूस ने 3 अप्रैल, 1984 को वैज्ञानिक स्काकोल, मालिनेश ब्रह्मनूर और अकेश शर्मा को अंतरिक्ष यान सोयुज टी-11 से चंद्रमा पर भेजने में सफलता हासिल की। इस कड़ी में चीन 2003 में मानवयुक्त यान चंद्रमा पर उतारने में सफल हो चुका है।

वैतनिक असमानता का दंश झेलने की मजबूरी



दीपिका अरोड़ा



महिला दिहाड़ी पुरुषों की अपेक्षा लगभग 85 प्रतिशत

समानता के महेनजर हुए ताजा सर्वेक्षण। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट बताती है कि विश्वभर में किसी कार्य हेतु पुरुषों को यदि 100 रुपये मिलते हैं तो महिलाओं को प्रदत्त श्रमदेय 73 रुपये (भारत में 71 रुपये) रहता है।

नैसर्कॉम की रिपोर्ट के अनुसार, देश की तकनीकी उद्यमिता में लगभग 30 प्रतिशत महिलाएं सम्मिलित हैं लेकिन उनका औसत वेतन पुरुषों से 29 प्रतिशत कम है। रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक, रिटेल वर्कफोर्स में महिला सहभागिता 70 प्रतिशत होने के बावजूद उनका वेतन पुरुषों की अपेक्षा 33 प्रतिशत कम है। मासिक आय का यह अंतर कृषि क्षेत्र में 3,812 रुपये, मैनुफैक्चरिंग में 5,904 रुपये, सर्विस सेक्टर में 4,435 रुपये तथा ट्रेडिंग में 6,020 रुपये है।

वर्ल्डइन्वैस्टमेंट रिपोर्ट के मुताबिक, देश की कुल श्रमिक आय में महिलाओं की हिस्सेदारी मात्र 18 प्रतिशत है, क्योंकि अधिकांश महिलाएं कम आय वाले व्यवसाय से ताल्लुक रखती हैं। इस संदर्भ में भारतीय ग्राम्य भूभागों का संज्ञान लेते आसित पुरुष दिहाड़ी 393 रुपये है तथा महिला श्रमदेय 265 रुपये है। शहरी क्षेत्रों में यह क्रमशः 483 तथा 333 रुपये है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के अनुसार, सांख्यिक अंतर केल राज्य में दृष्टिगोचर है। यहाँ गांवों में पुरुषों का औसत पारिश्रमिक 842 रुपये (प्रतिदिन) है तो महिलाओं का 434 रुपये।

पंजाब, हरियाणा, हिमाचल तथा राजस्थान में

महिला दिहाड़ी पुरुषों की अपेक्षा लगभग 85 प्रतिशत होने के कारण स्थिति बेहतर आंक सकते हैं। गुजरात, मध्यप्रदेश, झारखंड में यह 80 प्रतिशत तथा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल में पुरुषों के मुकाबले 70 प्रतिशत है। उत्तराखंड देश का एकमात्र राज्य है, जहाँ महिला श्रमदेय पुरुषों के मुकाबले अधिक पाया गया। 19 में से 11 बड़े राज्यों के मध्य स्थित अंतर वर्ष 2011-12 की अपेक्षा और बढ़ा है। पं. बंगाल, गुजरात, छत्तीसगढ़ में यह 10 प्रतिशत से अधिक रहा।

मैकेंजी की ताजा रिपोर्टनुसार, विश्वभर में महिलाओं की वरिष्ठ पदों पर भागीदारिता मात्र 14 प्रतिशत है, जिसके चलते मानदेय निर्धारित करने में 86 प्रतिशत पुरुषों की भूमिका प्रभावी हो जाती है। करिअर की अपेक्षा परिवार महिलाओं की प्राथमिकता है; वैतनिक भेद के पीछे यह मानसिकता भी प्रबल रहती है।

राष्ट्रीय स्तर पर जांचें तो मुख्य कारण हैं समाज में व्याप्त पितृसत्तात्मक सोच। इसके चलते महिलाओं को नियुक्ति, पदोन्नति, भुगतान आदि में पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता है, भले ही उनकी योग्यता-अनुभव पुरुष सहयोगियों के समकक्ष हो। पारिवारिक जिम्मेदारियों के दृष्टिगत दीर्घकालीन अवकाश, नौकरी के स्वल्प-समय संबंधी पावर्दी, प्रशिक्षण तथा शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त समय न निकाल पाना, परिवहन उपलब्धता-सुरक्षा के दृष्टिगत समस्याएं पेश आना, मौक़े अपेक्षाकृत कम होने के कारण ऊंचे वेतनमान के लिए अधिक मोलभाव न कर पाना आदि अनेकानेक कारण

इस अंतर को बढ़ावा देते हैं। कानूनी स्थिति देखें तो 1976 में पारित 'समान पारिश्रमिक अधिनियम' सार्वजनिक अथवा निजी सभी संगठनों के नियमित-अनियमित कर्मचारियों को दायरे में लेते हुए, बिना किसी लिंग भेदभाव समान कार्यों के लिए समान वेतन प्राप्त करना सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 (डी) तथा अनुच्छेद 42 इस विषय में समानता की पूर्ण गारंटी देते हैं। वर्ष 2013 में पारित 'यौन उर्ध्वीन (निवारण, प्रतिषेध तथा प्रतिरोध) अधिनियम' कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा आवश्यक बनाने सहित वेतनमान समानता भी सुनिश्चित करता है।

सामयिक आवश्यकता के महेनजर वर्ष 2017 को संशोधित 'मातृत्व लाभ अधिनियम' के तहत मातृत्व अन्वेषण की अवधि 12 सप्ताह से बढ़कर 26 सप्ताह कर दी गई। इसी प्रकार, वर्ष 2022 में 'भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड' (बीसीसीआई) ने 'भुगतान समता नीति' के अंतर्गत, केंद्रीय रूप से अनुबंधित महिला-पुरुष खिलाड़ियों को समान फीस देने संबंधी घोषणा की। किंतु मजदूर कानून बनाने भर से इस अंतर को घटाना संभव नहीं है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी 'भारत में महिला एवं पुरुष 2022 रिपोर्ट' बताती है, विगत एक दशक में महिला-पुरुषों के मध्य वेतन असमानता बढ़ी है। उच्च वेतन स्तर पर अंतराल और अधिक बढ़ गया।

भेदभाव की गहरी खाई पटने हेतु समग्र मानसिकता में बदलाव लाना आवश्यक है। समावेशी तथा सुसंचालित राजनीतिक-सामाजिक नीतियां सर्वपक्षीय असमानता दूर करने में निर्णायक योगदान दे सकती हैं। मौजूदा कानूनों में अपेक्षित संशोधन करने के साथ समयानुकूल नव विधान लाना एवं संबद्ध कानूनों को कड़ाईपूर्वक लागू करना समय की मांग है। आवश्यक है कि अंतरिक्ष कर्मचारियों को कोशल एवं ज्ञानवृद्धि हेतु प्रशिक्षण तथा विकास के पर्याप्त अवसर मुहैया करवाए जाएं, जो कि करिअर में आगे बढ़ने तथा बेहतर अवसर पाने में सहकृष्ण सिद्ध हो सकें।

पिछले 3 दशकों में सदन की घटती बैठकें



सन्त कुमार जैन

मध्यप्रदेश विधानसभा की 15 वीं विधानसभा का आखिरी सत्र मंगलवार से शुरू हो गया है। मात्र 5 दिनों मानसून सत्र आहूत किया गया है। जो पहले ही 7दिन हंगामे के कारण स्थगित हो गया। पिछले 30 वर्षों में सबसे कम बैठकें इस वर्ष आयोजित की गई हैं। नियम के अनुसार 1 साल में 120 बैठकें आयोजित करने का नियम है। लेकिन आखिरी सत्र को मिलाकर मध्यप्रदेश विधानसभा की केवल 75 बैठकें ही आहूत की गई हैं। इसमें भी 45 दिन की बैठकें में हो-रुख और हंगामा होता रहा। मात्र 30 दिन ही प्रश्न उत्तर और बिलों पर चर्चा हुई है। 45 दिन कोई भी विधि-विधार्थ कार्य नहीं हुआ। यह हाल केवल मध्यप्रदेश का नहीं है। पिछले 30 वर्षों में विधानसभा और लोकसभा में बैठकों की संख्या ने निरंतर कमी हो रही है। पिछले 10 वर्षों में लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें पिछले वर्षों की तुलना में बहुत कम हुई हैं।

लोकसभा, राज्य सभा और विधान सभाओं में जिस तरीके से सदन के अंदर बैठकें के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में हंगामे होते हैं। बिलों को जिस तरह बिना किसी विचार विमर्श के हो छेड़े के बीच सदन से पास करा लिया जाता है। सांसद और विधायकों को अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का मौका भी सदन में नहीं मिलता है। प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर के जो नियम और कानून बनाए जा रहे हैं। उन पर भी निर्वाचित प्रतिनिधियों को ना तो अध्ययन करने और नाही विचार रखने का उन्हें मौका 2दिया जाता है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे चिंताजनक स्थिति है। कुछ वर्षों से यह कहा जाता है, कि सरकार की मंशा के अनुरूप लोकसभा अध्यक्ष हों, या विधानसभाओं के अध्यक्ष हों। वह सरकार की मंशा के अनुरूप सदन की बैठकें बुलाते हैं। जबकि लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है, कि सदस्यों को अपनी बात कहने का अवसर सदन में पर्याप्त रूप से मिले। जो भी बिल सदन में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उनमें पर्याप्त चर्चा हो। चर्चा के पक्षत ही बिलों को पारित किया जाए। इसके लिए बड़ी मोटी मोटी कितानों में संसद और विधानसभाओं ने अपने नियम भी बना रखे हैं। इन नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष की ही होती है। लेकिन देखा जा रहा है, कि सत्ता पक्ष के दबाव में लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष अपने कर्तव्यों का निर्वहन वैसा नहीं कर पा रहे हैं, जैसा उन्हें करना चाहिए। लोकसभा और विधानसभा में जिस तरह से बिना चर्चा के कानून पारित किए जा रहे हैं। यह पूर्णतः असंवैधानिक और लोकतांत्रिक

व्यवस्था के विपरीत है। यदि लोकसभा, विधानसभा और सरकार अपने ही बनाए गए नियमों का पालन नहीं करेगी। तो इस स्थिति में किस तरह से यह आशा की जा सकती है, कि विपक्षी दल और नागरिक नियमों और कानूनों का पालन करेंगे। नियम कानून और व्यवस्था नैतिकता के आधार पर चलती हैं। डंडा मारकर नियम और कानून का पालन नहीं करया जा सकता है। जिस तरह से सदन में बैठकों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। नागरिकों के अधिकारों के हनन की बात,यदि हम छोड़ भी दें। विधायक और सांसद भी अपने अधिकारों की रक्षा सदन में नहीं कर पा रहे हैं। जिन नागरिकों ने उन्हें अपने अधिकार से निर्वाचित किया है। वह सदन में अपनी बात ही नहीं कह पाते हैं। सांसद और विधायक जो प्रश्न लगाते हैं। उन्हें ताराकित और अताराकित प्रश्न के रूप में भी सदन में स्वीकार भी अपने अधिकारों की रक्षा सदन में नहीं कर पा रहे हैं। जिन नागरिकों ने उन्हें अपने अधिकार से निर्वाचित किया है। वह सदन में अपनी बात ही नहीं कह पाते हैं। सांसद और विधायक जो प्रश्न लगाते हैं। उन्हें ताराकित और अताराकित प्रश्न के रूप में भी सदन में स्वीकार भी अपने अधिकारों की रक्षा सदन में नहीं कर पा रहे हैं। जिन नागरिकों ने उन्हें अपने अधिकार से निर्वाचित किया है। वह सदन में अपनी बात ही नहीं कह पाते हैं। सांसद और विधायक जो प्रश्न लगाते हैं। उन्हें ताराकित और अताराकित प्रश्न के रूप में भी सदन में स्वीकार भी अपने अधिकारों की रक्षा सदन में नहीं कर पा रहे हैं। जिन नागरिकों ने उन्हें अपने अधिकार से निर्वाचित किया है। वह सदन में अपनी बात ही नहीं कह पाते हैं। सांसद और विधायक जो प्रश्न लगाते हैं। उन्हें ताराकित और अताराकित प्रश्न के रूप में भी सदन में स्वीकार भी अपने अधिकारों की रक्षा सदन में नहीं कर पा रहे हैं। जिन नागरिकों ने उन्हें अपने अधिकार से निर्वाचित किया है। वह सदन में अपनी बात ही नहीं कह पाते हैं। सांसद और विधायक जो प्रश्न लगाते हैं। उन्हें ताराकित और अताराकित प्रश्न के रूप में भी सदन में स्वीकार भी अपने अधिकारों की रक्षा सदन में नहीं कर पा रहे हैं। जिन नागरिकों ने उन्हें अपने अधिकार से निर्वाचित किया है। वह सदन में अपनी बात ही नहीं कह पाते हैं। सांसद और विधायक जो प्रश्न लगाते हैं। उन्हें ताराकित और अताराकित प्रश्न के रूप में भी सदन में स्वीकार भी अपने अधिकारों की रक्षा सदन में नहीं कर पा रहे हैं। जिन नागरिकों ने उन्हें अपने अधिकार से निर्वाचित किया है। वह सदन में अपनी बात ही नहीं कह पाते हैं। सांसद और विधायक जो प्रश्न लगाते हैं। उन्हें ताराकित और अताराकित प्रश्न के रूप में भी सदन में स्वीकार भी अपने अधिकारों की रक्षा सदन में नहीं कर पा रहे हैं। जिन नागरिकों ने उन्हें अपने अधिकार से निर्वाचित किया है। वह सदन में अपनी बात ही नहीं कह पाते हैं। सांसद और विधायक जो प्रश्न लगाते हैं। उन्हें ताराकित और अताराकित प्रश्न के रूप में भी सदन में स्वीकार भी अपने अधिकारों की रक्षा सदन में नहीं कर पा रहे हैं। जिन नागरिकों ने उन्हें अपने अधिकार से निर्वाचित किया है। वह सदन में अपनी बात ही नहीं कह पाते हैं। सांसद और विधायक जो प्रश्न लगाते हैं। उन्हें ताराकित और अताराकित प्रश्न के रूप में भी सदन में स्वीकार भी अपने अधिकारों की रक्षा सदन में नहीं कर पा रहे हैं। जिन नागरिकों ने उन्हें अपने अधिकार से निर्वाचित किया है। वह सदन में अपनी बात ही नहीं कह पाते हैं। सांसद और विधायक जो प्रश्न लगाते हैं। उन्हें ताराकित और अताराकित प्रश्न के रूप में भी सदन में स्वीकार भी अपने अधिकारों की रक्षा सदन में नहीं कर पा रहे हैं। जिन नागरिकों ने उन्हें अपने अधिकार से निर्वाचित किया है। वह सदन में अपनी बात ही नहीं कह पाते हैं। सांसद और विधायक जो प्रश्न लगाते हैं। उन्हें ताराकित और अताराकित प्रश्न के रूप में भी सदन में स्वीकार भी अपने अधिकारों की रक्षा सदन में नहीं कर पा रहे हैं। जिन नागरिकों ने उन्हें अपने अधिकार से निर्वाचित किया है। वह सदन में अपनी बात ही नहीं कह पाते हैं। सांसद और विधायक जो प्रश्न लगाते हैं। उन्हें ताराकित और अताराकित प्रश्न के रूप में भी सदन में स्वीकार भी अपने अधिकारों की रक्षा सदन में नहीं कर पा रहे हैं। जिन नागरिकों ने उन्हें अपने अधिकार से निर्वाचित किया है। वह सदन में अपनी बात ही नहीं कह पाते हैं। सांसद और विधायक जो प्रश्न लगाते हैं। उन्हें ताराकित और अताराकित प्रश्न के रूप में भी सदन में स्वीकार भी अपने अधिकारों की रक्षा सदन में नहीं कर पा रहे हैं। जिन नागरिकों ने उन्हें अपने अधिकार से निर्वाचित किया है। वह सदन में अपनी बात ही नहीं कह पाते हैं। सांसद और विधायक जो प्रश्न लगाते हैं। उन्हें ताराकित और अताराकित प्रश्न के रूप में भी सदन में स्वीकार भी अपने अधिकारों की रक्षा सदन में नहीं कर पा रहे हैं। जिन नागरिकों ने उन्हें अपने अधिकार से निर्वाचित किया है। वह सदन में अपनी बात ही नहीं कह पाते हैं। सांसद और विधायक जो प्रश्न लगाते हैं। उन्हें ताराकित और अताराकित प्रश्न के रूप में भी सदन में स्वीकार भी अपने अधिकारों की रक्षा सदन में नहीं कर पा रहे हैं। जिन नागरिकों ने उन्हें अपने अधिकार से निर्वाचित किया है। वह सदन में अपनी बात ही नहीं कह पाते हैं। सांसद और विधायक जो प्रश्न लगाते हैं। उन्हें ताराकित और अताराकित प्रश्न के रूप में भी सदन में स्वीकार भी अपने अधिकारों की रक्षा सदन में नहीं कर पा रहे हैं। जिन नागरिकों ने उन्हें अपने अधिकार से निर्वाचित किया है। वह सदन में अपनी बात ही नहीं कह पाते हैं। सांसद और विधायक जो प्रश्न लगाते हैं। उन्हें ताराकित और अताराकित प्रश्न के रूप में भी सदन में स्वीकार भी अपने अधिकारों की रक्षा सदन में नहीं कर पा रहे हैं। जिन नागरिकों ने उन्हें अपने अधिकार से निर्वाचित किया है। वह सदन में अपनी बात ही नहीं कह पाते हैं। सांसद और विधायक जो प्रश्न लगाते हैं। उन्हें ताराकित और अताराकित प्रश्न के रूप में भी सदन में स्वीकार भी अपने अधिकारों की रक्षा सदन में नहीं कर पा रहे हैं। जिन नागरिकों ने उन्हें अपने अधिकार से निर्वाचित किया है। वह सदन में अपनी बात ही नहीं कह पाते हैं। सांसद और विधायक जो प्रश्न लगाते हैं। उन्हें ताराकित और अताराकित प्रश्न के रूप में भी सदन में स्वीकार भी अपने अधिकारों की रक्षा सदन में नहीं कर पा रहे हैं। जिन नागरिकों ने उन्हें अपने अधिकार से निर्वाचित किया है। वह सदन में अपनी बात ही नहीं कह पाते हैं। सांसद और विधायक जो प्रश्न लगाते हैं। उन्हें ताराकित और अताराकित प्रश्न के रूप में भी सदन में स्वीकार भी अपने अधिकारों की रक्षा सदन में नहीं कर पा रहे हैं। जिन नागरिकों ने उन्हें अपने अधिकार से निर्वाचित किया है। वह सदन में अपनी बात ही नहीं कह पाते हैं। सांसद और विधायक जो प्रश्न लगाते हैं। उन्हें ताराकित और अताराकित प्रश्न के रूप में भी सदन में स्वीकार भी अपने अधिकारों की रक्षा सदन में नहीं कर पा रहे हैं। जिन नागरिकों ने उन्हें अपने अधिकार से निर्वाचित किया है। वह सदन में अपनी बात ही नहीं कह पाते हैं। सांसद और विधायक जो प्रश्न लगाते हैं। उन्हें ताराकित और अताराकित प्रश्न के रूप में भी सदन में स्वीकार भी अपने अधिकारों की रक्षा सदन में नहीं कर पा रहे हैं। जिन नागरिकों ने उन्हें अपने अधिकार से निर्वाचित किया है। वह सदन में अपनी बात ही नहीं कह पाते हैं। सांसद और विधायक जो प्रश्न लगाते हैं। उन्हें ताराकित और अताराकित प्रश्न के रूप में भी सदन में स्वीकार भी अपने अधिकारों की रक्षा सदन में नहीं कर पा रहे हैं। जिन नागरिकों ने उन्हें अपने अधिकार से निर्वाचित किया है। वह सदन में अपनी बात ही नहीं कह पाते हैं। सांसद और विधायक जो प्रश्न लगाते हैं। उन्हें ताराकित और अताराकित प्रश्न के रूप में भी सदन में स्वीकार भी अपने अधिकारों की रक्षा सदन में नहीं कर पा रहे हैं। जिन नागरिकों ने उन्हें अपने अधिकार से निर्वाचित किया है। वह सदन में अपनी बात ही नहीं कह पाते हैं। सांसद और विधायक जो प्रश्न लगाते हैं। उन्हें ताराकित और अताराकित प्रश्न के रूप में भी सदन में स्वीकार भी अपने अधिकारों की रक्षा सदन में नहीं कर पा रहे हैं। जिन नागरिकों ने उन्हें अपने अधिकार से निर्वाचित किया है। वह सदन में अपनी बात ही नहीं कह पाते हैं। सांसद और विधायक जो प्रश्न लगाते हैं। उन्हें ताराकित और अताराकित प्रश्न के रूप में भी सदन में स्वीकार भी अपने अधिकारों की रक्षा सदन में नहीं कर पा रहे हैं। जिन नागरिकों ने उन्हें अपने अधिकार से निर्वाचित किया है। वह सदन में अपनी बात ही नहीं कह पाते हैं। सांसद और विधायक जो प्रश्न लगाते हैं। उन्हें ताराकित और अताराकित प्रश्न के रूप में भी सदन में स्वीकार भी अपने अधिकारों की रक्षा सदन में नहीं कर पा रहे हैं। जिन नागरिकों ने उन्हें अपने अधिकार से निर्वाचित किया है। वह सदन में अपनी बात ही नहीं कह पाते हैं। सांसद और विधायक जो प्रश्न लगाते हैं। उन्हें ताराकित और अताराकित प्रश्न के रूप में भी सदन में स्वीकार भी अपने अधिकारों की रक्षा सदन में नहीं कर पा रहे हैं। जिन नागरिकों ने उन्हें अपने अधिकार से निर्वाचित किया है। वह सदन में अपनी बात ही नहीं कह पाते हैं। सांसद और विधायक जो प्रश्न लगाते हैं। उन्हें ताराकित और अताराकित प्रश्न के रूप में भी सदन में स्वीकार भी अपने अधिकारों की रक्षा सदन में नहीं कर पा रहे हैं। जिन नागरिकों ने उन्हें अपने अधिकार से निर्वाचित किया है। वह सदन में अपनी बात ही नहीं कह पाते हैं। सांसद और विधायक जो प्रश्न लगाते हैं। उन्हें ताराकित और अताराकित प्रश्न के रूप में भी सदन में स्वीकार भी अपने अधिकारों की रक्षा सदन में नहीं कर पा रहे हैं। जिन नागरिकों ने उन्हें अपने अधिकार से निर्वाचित किया है। वह सदन में अपनी बात ही नहीं कह पाते हैं। सांसद और विधायक जो प्रश्न लगाते हैं। उन्हें ताराकित और अताराकित प्रश्न के रूप में भी सदन में स्वीकार भी अपने अधिकारों की रक्षा सदन में नहीं कर पा रहे हैं। जिन नागरिकों ने उन्हें अपने अधिकार से निर्वाचित किया है। वह सदन में अपनी बात ही नहीं कह पाते हैं। सांसद और विधायक जो प्रश्न लगाते हैं। उन्हें ताराकित और अताराकित प्रश्न के रूप में भी सदन में स्वीकार भी अपने अधिकारों की रक्षा सदन में नहीं कर पा रहे हैं। जिन नागरिकों ने उन्हें अपने अधिकार से निर्वाचित किया है। वह सदन में अपनी बात ही नहीं कह पाते हैं। सांसद और विधाय

कहां गए धर्म के ठेकेदार : धर्म को लेकर राजनीति करने वाले मौन क्यों...?

माही की गूँज, राजालपुर।
अजय राज केवट

प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह ने हाल ही में राजनीतिक दिखाने के लिए सीधी पेशाब कांड के पीड़ित के पैर धोकर सर्वाधिक माफी मांग कर अपने कार्य की इतिश्री कर ली। लेकिन प्रदेश में आज भी ऐसे कई आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं जिन्होंने बड़े-बड़े कांड किये हैं चाहे वह बलात्कार ही, भ्रष्टाचार हो, पुलिस की गुंडागर्दी हो या अन्य। यहाँ माया जी की राजनीति और पुलिस विभाग में अपनी पकड़ फिस्सडी साबित होते नजर आ रही है।

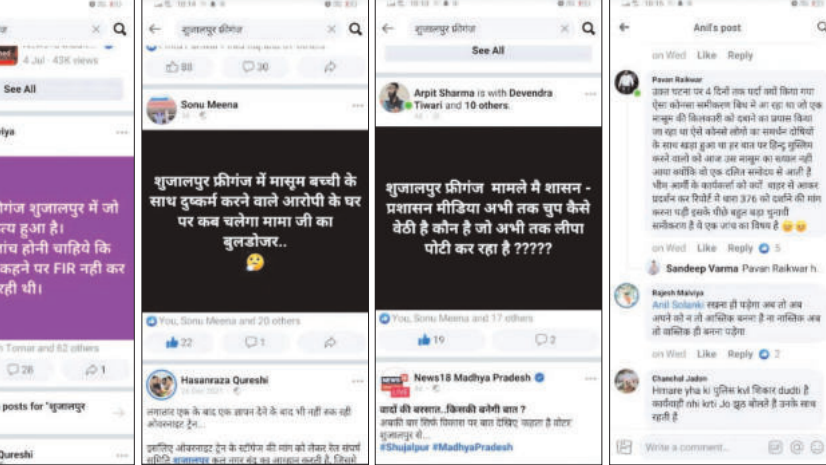
हाल ही में राजालपुर मंडी फ्रीगंज में साई मंदिर के पुजारी संतोष ब्राह्मण पर आरोप लगा कि, उसने 4 वर्ष की मासूम के साथ बलात्कार किया है। जिस मामले में पुलिस को कार्रवाई करने में खरा उतरना था, लेकिन राजालपुर मंडी पुलिस प्रशासन ने अपना ढील-पोल रवैया अपनाया। मासूम के परिजन ने शाजापुर महिला थाने में जाकर एफआईआर भी दर्ज करवाई, जिसके बाद

आरोपी को पकड़ कर न्यायलय में पेश किया गया, जहाँ न्यायलय द्वारा आरोपी को जेल भेजा गया।

4 वर्ष की मासूम को कब मिलेगा न्याय

कुछदिन पूर्व सीधी जिले में पेशाब कांड को लेकर मुख्यमंत्री व गृहमंत्री एक्शन मोड में आकर भाजपा नेता के घर पर बुलडोजर चलाकर आदिवासी को न्याय तो दिला दिया, मगर राजालपुर क्षेत्र की घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने रेपकांड के आरोपी का मकान क्यों जमींदोज नहीं किया...? या फिर सब कुछ जान कर भी नजरअंदाज किया गया, यह एक बड़ा प्रश्न है।

राजालपुर के स्थानीय नेताओं व प्रशासन को आखिर किस बड़ी घटना का इंतजार है। क्या मासूम की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद में प्रशासन हलकत में आया या फिर यँ ही शहर की मासूम इन दरिदो की



हवस का शिकार होती रहेगी...?

कहां गए धर्म के ठेकेदार...?

फतला-ढीमका घटनाओं दिखोरा पीट-पीटकर व गाय को लेकर प्रदर्शन कर व सोशल मीडिया पर अपने राजनीतिक चमकाने वाले समाज व हिंदुत्व का ठेका

लिए घूम रहे ठेकेदारों ने आखिर मासूम के साथ में हुए बलात्कार को लेकर मौन क्यों धारण कर रखा है...? यह भी आमजन के मुह पर चर्चा का विषय जोरों पर चल रहा है।

वहीं हिंदू जागरण मंच ने कलापीपल तहसील में हुए बलात्कार के आरोपी आमीन

पिता आफजल खा का मकान ध्वस्त करने व उस पर एनएसए की धारा लगाने की बात को लेकर रेली निकाल कर ज्ञापन दिया। लेकिन 4 वर्ष की बालिका के सम्मान को लेकर किसी भी संगठन की निंद, नहीं खुली। ये भी आम जन के मुह पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

हिन्दू नेता पर जानलेवा हमले के मामले में सूफा गुप के असजद, रिजवान और समीर को दस-दस वर्ष, शाहिद को मिली तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा

माही की गूँज, रतलाम।

आतंकी गतिविधियों में लिस सूफा गुप चलाने वाले असजद, रिजवान और समीर उर्फ राजा को हिन्दू जागरण मंच के संयोजक राजेश कटारिया को जान से मारने की नीयत से फायर करने के मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा ने दस दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामले के अन्य आरोपी शाहिद खान को आर्य एक्ट के मामले में तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, जबकि एक आरोपी अनवर खान उर्फ अन्नू को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया है।

2013 में हुआ था हिन्दू नेता पर जानलेवा हमला

आरोपियों ने 29 जुलाई 2013 को हिन्दू नेता राजेश कटारिया की हत्या करने का प्रयास किया था। इस संवेदनशील मामले में आने वाले निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस प्रशासन ने मंगलवार सुबह से जिला न्यायालय परिसर में कड़े सुरक्षा प्रबंध किए थे। पांचों अभियुक्तों को कड़ी सुरक्षा में न्यायालय में लाया गया, जहाँ न्यायाधीश वर्मा ने भोजनावकाश के बाद उन्हें सजा देने का फैसला किया। न्यायालय का विस्तृत निर्णय काफी देर के बाद अधिवक्ताओं और अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध हो पाया।

प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक संजीव सिंह

चौहान ने बताया कि, घटना दिनांक 29 जुलाई 2013 की शाम करीब पौने पांच बजे राजेश कटारिया मोटर साइकिल से सालाखेडी के पास इटवा रोड गोदाम से अपने दूसरे संस्थान फ्रेन्ड्स ऑटोमोबाइल की तरफ जा रहे थे कि, अचानक पीछे से दो अज्ञात मोटर साइकिल सवारों ने उन पर पिस्टल से दो फायर किए। ये गोलियां राजेश के बाएं हाथ के कन्धे और कोहनी में लगीं। खतरे को भांप कर राजेश ने अपनी मोटर साइकिल तेजी से भगाई, लेकिन हमलावरों ने फिर भी उनका पीछा किया और पटवा अभिकरण के पास उन पर फिर से फायर किया और मौके से भाग गए।

जाँच में सामने आया अल सुफुफ़ा संगठन का नाम

घटना की रिपोर्ट के बाद जब पुलिस ने अनुसन्धान किया तो पता चला कि, राजेश कटारिया पर हमला करने वाले समीर उर्फ राजा पिता बारीक खान और रिजवान खान पिता रमजानी खान थे। समीर मोटर साइकिल चला रहा था, जबकि रिजवान ने पीछे बैठकर राजेश पर फायर किए थे। उक्त दोनों आरोपियों से पुछताछ के बाद पता चला कि इस हमले का मुख्य षडयंत्रकर्ता अल सुफुफ़ा नामक आतंकी संगठन बनाने वाला असजद उर्फ अज्जत पिता जहूर खान था। असजद ने अपने घर पर एक मीटिंग की जिसमें आरोपी शाहिद, रिजवान और समीर आदि शामिल थे। इस मीटिंग में यह तय हुआ कि चूँकि राजेश कटारिया हिन्दू संगठन का

नेता है और मुसलमानों के खिलाफ बोलता है, इसलिए इसे खत्म करना है। मीटिंग में बनी योजना के मुताबिक पहले अनवर और शाहिद ने राजेश कटारिया की निगरानी की और फिर समीर और रिजवान ने उन पर हमला किया।

ये मिली सजा

प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों तथा बचाव पक्ष के तर्कों की सुनवाई के पश्चात विद्वान तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा ने मुख्य षडयंत्रकर्ता असजद उर्फ अज्जत पिता जहूर खान को भादवि की धारा 307 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास और पांच सौ रुपए अर्थदंड तथा आर्य एक्ट की धारा 25 के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास तथा आर्य एक्ट की धारा 27 के तहत 5 वर्ष के कठोर कारावास और पांच सौ रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। इसी प्रकार रिजवान खान पिता रमजानी खान को धारा 307 के तहत दस वर्ष कारावास, आर्य एक्ट की धारा 25 के तहत तीन वर्ष कारावास और पांच पांच सौ रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। तीसरे मुख्य अभियुक्त समीर उर्फ राजा पिता बारीक खान को धारा 307 में दस वर्ष कारावास और पांचसौ रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले के चौथे अभियुक्त शाहिद खान पिता फरीद खान को आर्य एक्ट की धारा 25 के तहत दोष सिद्ध करार देते हुए 3 वर्ष के



कारावास और पांच सौ रुपए अर्थदंड की सजा दी गई। जबकि पांचवे अभियुक्त अनवर खान उर्फ अन्नू पिता युसुफ खान को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया। अभियुक्तों को सजा सुनाए जाने के तत्काल बाद दोषसिद्ध अभियुक्तों को पुलिस की कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया गया।

उल्लेखनीय है कि, इस प्रकरण के आरोपियों में जहाँ असजद अल सुफुफ़ा जैसे आतंकी गुप का कर्ता धर्ता हैं, वहीं एक अन्य आरोपी रिजवान खान पूर्व में बजरंग दल नेता कपिल राठौड़ की हत्या में दोषसिद्ध होकर आजीवन कारावास का सजायापता मुजरिम है। प्रकरण के विचारण के दौरान भी वह उज्जैन की भेरुगढ़ सेन्ट्रल जेल में ही बन्द था।

स्कूल के प्रिंसिपल की मनमानी के आगे विद्यार्थी का हो रहा भविष्य खराब

माही की गूँज, राजापुर।

जिले के ग्राम कड़वाला में स्थित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के नुमाइंदे शासन के नियमों को ताक पर रखकर अपनी मनमानी से स्कूल संचालित कर रहे हैं। आलम यह है कि, ग्राम कड़वाला के रहने वाले छात्र संदीप भिलाला को स्कूल से टीसी नहीं मिल पा रही है जिसके कारण सरकारी स्कूल में संदीप को दाखिला नहीं हो पा रहा है। वर्ष भर से स्कूल की मनमानी के चलते बच्चों का भविष्य अंधकार में है। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह निजी स्कूल में फीस देने में असमर्थ है।



वहीं स्कूल संचालक राधेश्याम दशरथिया का कहना है कि, पूरा पैसा जमा होने के बाद ही टीसी दूंगा। छात्र संदीप के पिता और संदीप ने माही की गूँज को बताया कि, यदि टीसी नहीं मिलती तो मेरे बेटा का पूरा एक वर्ष खराब हो जायेगा, मेरे 2 बेटे स्कूल में पढ़ रहे थे लेकिन मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण मैंने पढ़ाई से एक बच्चे को वंचित कर दिया लेकिन दूसरे को पढ़ाना चाहते हैं तो सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाना जा रहा था,



लेकिन सरस्वती शिशु मंदिर के प्रिंसिपल राधेश्याम दशरथिया का कहना है कि पूरी फीस जमा होने के बाद ही टीसी दी जाएगी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर छात्र संदीप ने राजालपुर सिटी थाने पर आवेदन भी दिया है। अब देखना ये होगा की सरस्वती शिशु मंदिर कड़वाला के प्रिंसिपल की ऐसी की मनमानी चलती रहेगी या छात्र संदीप का भविष्य बर्बाद होने से बचा लिया जाएगा।

वही छात्र संदीप के पिता राधेश्याम भिलाला ने स्कूल प्रिंसिपल राधेश्याम दशरथिया पर फीस के आरोप लगाते हुए बताया कि, मैं एक बार स्कूल में फीस जमा करने के लिए गया था, मुझे 15 हजार रुपए बकाया बताया, तब मेरे पास पूरे पैसे नहीं

जैन सोशयल ग्रुप सुभाष स्कूल में किया पाठ्य सामग्री का वितरण

माही की गूँज,

जावरा। जैन सनातन धर्म में पांच माह का चार्तुमास काल चल रहा है, वहीं चार्तुमास धर्म, ध्यान, त्याग, तपस्या, आराधना और पवित्र सावन माह जिसमें भगवान शिव का आराधना का समय है ऐसे समय में मानवसेवा का संकल्प निश्चित रूप से आत्म उद्धारक कार्य है। आज निश्चित रूप से जैन सोशयल ग्रुप जावरा मैत्री परिवार द्वारा पिछले 6 वर्षों से गोद लिए गए सुभाष एकीकृत विद्यालय में प्रतिवर्ष अध्ययनरत बच्चों को कॉपी, कमास, बालपेन, कॉपी कवर, पेन्सिल, पानी की बॉटल, पेन्सिल कवर आदि पाठ्य सामग्री वितरण कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया है। इसके लिए जैन सोशयल ग्रुप जावरा मैत्री के सभी सदस्य साधुवाद के पात्र हैं। उक्त विचार जैन सोशयल ग्रुप जावरा मैत्री द्वारा सुभाष एकीकृत विद्यालय में अध्ययनरत 110 बच्चों को स्कूल सामग्री वितरण कार्यक्रम में सांसद प्रतिनिधि प्रदीप चौधरी ने व्यक्त किए। इस अवसर पर जैन सोशयल ग्रुप इन्टरनेशनल फेडरेशन मध्यप्रदेश रिजन के जावरा झोन कोर्डिनेटर शेखर नाहर, जैन सोशयल ग्रुप फेडरेशन के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय सह सचिव अनिल धारीवाल, प्रदेश रिजन उपाध्यक्ष संदीप रांका, रिजन के पूर्व कोषाध्यक्ष पंकज काठेड व महंत स्वामी सुधाकर पूरी जी ने भी सम्बोधित किया।



जैन सोशयल ग्रुप जावरा मैत्री के सचिव अर्पल कोचुद्र एवं प्रचार सचिव मनीष धारीवाल ने बताया कि, जैन सोशयल ग्रुप जावरा मैत्री परिवार द्वारा पिछले 6 वर्षों से लगातार सुभाष एकीकृत विद्यालय में पूर्व में स्टील फर्नीचर, पंखे, मेटांग के साथ प्रतिवर्ष पाठ्य सामग्री के साथ आवश्यक सामग्री गुप के सदस्यों एवं दानदाताओं के सहयोग से भेंट करतें हैं। इस वर्ष भी जैन सोशयल ग्रुप मध्यप्रदेश रिजन की मासिक गतिविधि के अंतर्गत शैक्षणिक सामग्री वितरण के तहत आज गुप द्वारा सुभाष स्कूल में स्कूल सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम का शुभारम्भ अथितियों व पदाधिकारियों द्वारा माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। स्वागत भाषण जैन सोशयल ग्रुप मैत्री अध्यक्ष आलोक बरैया द्वारा दिया गया। इस दौरान स्कूल परिसर में पशियों के लिए चबूतरे पर मक्का डाली गई व पौधरोपण भी किया गया। इस अवसर पर गुप के सभी सदस्य उपस्थित थे। सुभाष स्कूल स्टीफ से राजेश अरोड़ा सर, खान सर, विमला मेहता, शर्मा मैडम, भटनगर मैडम ने सभी का स्वागत किया, अंत में सचिव अर्पल कोचुद्र ने आभार व्यक्त किया।

गांधी उद्यान को हजारों पक्षियों के शमशान मे बदल दिया, गोल्ड कॉप्लेक्स के लिए उद्योगपति को बेच दिया बगीचा

विधायक चेतन्य काश्यप के इशारों पर प्रशासन कर रहा गैर कानूनी अपराधिक कृत्य, आधी रात को बगीचे के 50 से अधिक पेड़ काट डाले



माही की गूँज, रतलाम।

नगर निगम के सामने स्थित गांधी उद्यान को गोल्ड कॉप्लेक्स बनाने के लिए बेच दिया गया। 19 अप्रैल की अधिरात्रि को गांधी उद्यान के आधे पेड़ काट दिए गए थे। मंगलवार की रात को शेष बचे हुए 70 से अधिक 50 वर्ष पुराने विशाल वृक्ष भी काट दिए गए। हजारों पक्षी मर गए, हजारों घायल हो गए तथा हजारों अंडे खत्म हो गये। पुरा बगीचा उजाड़ दिया गया। विधायक चेतन्य काश्यप के इशारों प्रशासन गैरकानूनी



अपराधिक कृत्य कर रतलाम के पर्यावरण का सर्वनाश कर रहा है। यह आरोप कांग्रेस महासचिव, पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने लगाया। सकलेचा ने कहा कि, 70 वर्ष पुराने गांधी उद्यान के 19 अप्रैल को जब 100 से अधिक विशाल वृक्ष काटे जांचे थे, तब प्रशासन ने इस प्रकरण की जांच कर बगीचा नहीं उजाड़ने का आश्वासन दिया था। पुलिस में लिखित शिकायत करने के बाद भी पेड़ काटने वाले नगर निगम तथा गोल्ड कॉप्लेक्स के निवेशक पर कोई कार्यवाही



नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार बगीचा बेचा नहीं जाता जा सकता है। लेकिन जिला प्रशासन ने सर्वे नंबर 100 पर स्थित 70 वर्ष पुराने गांधी उद्यान को गोल्ड कॉप्लेक्स के लिए आरक्षित कर ठेकेदार को बेचकर गैर कानूनी अपराधिक कार्य किया है। सकलेचा ने कहा कि, प्रशासन बेलगाम हो गया है और पूंजीपतियों की कठपुतली बन गया है। रतलाम विधायक चेतन्य काश्यप का मौन बताया है कि उनके इशारों पर प्रशासन नियम के विपरीत अपराधिक कृत्य

कर रहा है। मंगलवार रात को काटे गए पेड़ में हजारों पक्षी तो मर गए, हजारों घायल हो गए और हजारों अण्डे जिनमें पक्षियों का जन्म होना था उनकी भूषण हत्या हो गई। नगर विधायक चेतन्य काश्यप रतलाम के पर्यावरण के सर्वनाश पर भी अपने अहंकार की पुष्टि चाहते हैं। सकलेचा ने कहा कि, गांधी उद्यान को बचाने के लिए सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा और कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी।



नर्मदा-माही लिंक परियोजना की स्वीकृति पर जताया सीएम का आभार तहसील के साथ खेल स्टेडियम के लिए मुख्यमंत्री को दिया ज्ञापन

पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने समर्थकों के साथ सीएम को भेंट किया नर्मदा-माही माता का चित्र

माही की गूँज, धार/अमड़ोरा। विक्रमसिंह राठौर

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की जन-दर्शन यात्रा के दौरान खरेली फाटे पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य कमल यादव ने किसान भाइयों और सेकंडी युवाओं के साथ सीएम का भव्य स्वागत किया और नर्मदा माही लिंक परियोजना लागत 2 हजार 100 करोड़ की राशि मंजूर कर लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। साथ ही अमड़ोरा को तहसील बनाए जाने, महाविद्यालय, मण्डि व खेल स्टेडियम के लिए मांग रखते हुए ज्ञापन दिया। इस अवसर पर किसान मोर्चा के जिला



उपाध्यक्ष उकारलाल जाट, जिला महामंत्री जनपद सदस्य बलराम मकवाना, जनपद रतन लाल पाटीदार, भाजपा नेता मुकेश राठौर, सदस्य गलाल, युवा मोर्चा मण्डल अध्यक्ष

अर्पित शर्मा, किसान मोर्चा मण्डल महामंत्री मुकेश कुमावत, जिला कार्यकारणी सदस्य अशुल राठौर, मंडल महामंत्री मुकेश पाटीदार, मंडल उपाध्यक्ष रालपाल चावड़ा, रवि प्रजापत, अमित मोदी, कार्तिक धंगया, पूनमचंद पाटीदार, अरविंद जाट, मुकेश पटेल, केलाश चौहान, सुनील जाट, मंडल महामंत्री शंकर देवड़ा, शंकर हामड़, मुन्ना लाल यादव आदि अन्य कार्यकर्तागण मौजूद रहे। इस अवसर पर कमल यादव एवं समर्थकों के द्वारा पहले सीएम का स्वागत करते हुए गवली ब्रजवासी समाज के परंपरागत दुल्हे को पहनाए जाने वाला आकर्षक मोर पहनाया गया एवं माता नर्मदा-माही माता का चित्र भी भेंट किया।

भूमिपूजन कर कार्य शुरू करवाना भूल गए भाजपा के बड़े-बड़े नेता... भाजपा नेता आईने में लड्डू दिखाने का कर रहे कार्य

माही की गूँज, जोबट। अनिल हरवाल

जोबट विकासखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम बड़ागुड़ा पटेल फलिया की प्राथमिक स्कूल भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण गांव के लोगों के द्वारा शिक्षा विभाग में कई बार शिकायत करने के बाद राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग को



भवन निर्माण बनाने के लिए अनुमति तो दे दी लेकिन अभी तक भवन निर्माण के लिए फंड राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया गया। जिसके चलते भाजपा के नेता प्राथमिक स्कूल भवन का भूमि पूजन तो कर गए लेकिन अभी तक कार्य चालू नहीं किया गया। जिसका खामियाजा स्कूल में पढ़ने वाले छोटे-छोटे बच्चे जोबट से अलीराजपुर मार्ग पर 1 किलोमीटर दूर पैदल चलकर स्कूल

जाते हैं। जिसके चलते छोटे-छोटे बच्चे सड़क के किनारे चलते-चलते इधर उधर भी दौड़ने लगते हैं। जिसके चलते हादसा हो सकता है। तो जिम्मेदार कौन रहेगा। वहीं पर भाजपा सरकार केवल आईने में लड्डू दिखाने का कार्य कर रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि, प्राथमिक स्कूल बड़ागुड़ा के भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन 3 से 4 माह पहले किया था लेकिन अभी तक वहां पर कार्य चालू नहीं हुआ। जोबट विकासखंड में एक प्राथमिक स्कूल भवन निर्माण के लिए भाजपा के कई बड़े नेता जैसे सांसद गुमानसिंह डामोर, विधायक प्रतिनिधि विशाल रावत के साथ कई भाजपा नेता मिलकर अलग-अलग स्थानों पर जाकर प्राथमिक स्कूलों के भवन का भूमि पूजन के कार्य किए लेकिन आज तक एक भी कार्य चालू नहीं हुआ।

युवक को तलवे चाटने पर किया मजबूर, 2 अपराधियों पर लगी रासुका

ग्वालियर।

चार पहिया वाहन में बबरता से मारपीट करने और तलवे चटवाने वाले दो गुंडों पर रासुका लगाई गई है। पूछताछ में दोनों गुंडों ने पुलिस को बताया कि, इनके कहने पर ही मुख्य आरोपी ने मोहसिन खान से कार में बबरता की थी। उसे पहले चपलों से पीटा फिर तलवे चटवाए, जिस वाहन में बबरता हुई, वह इन्हीं गुंडों का है। दोनों पर पूर्व में बस लूट, आर्म एक्ट, डकैती जैसे गंभीर अपराध दर्ज हैं।

ग्वालियर में युवक से बबरता कर तलवे चटवाने का वीडियो पूरे प्रदेश में चर्चित रहा था। सीपी कांड के बाद ग्वालियर में बबरता का यह वीडियो सामने आने से पुलिस अलर्ट हुई थी। पुलिस ने शनिवार दोपहर तक मुख्य आरोपी, अमित गुर्जर, तेजेंद्र गुर्जर और सुदीप गुर्जर को पकड़ लिया था। मुख्य आरोपी को कोर्ट में पेश कर बाल सुधार गृह भेजा गया है। उसकी उम्र 17 वर्ष 11 माह बताई गई है। सुदीप को जेल भेजा गया। वारदात में शामिल अमित पर पूर्व के दो और

तेजेंद्र पर छह अपराध दर्ज हैं। ग्वालियर एसपी राजेश सिंह चंदेल ने बताया कि, वारदात की प्लानिंग अमित और तेजेंद्र ने की थी। 23 जून को आरोपितों ने पहले शराब पी। मुख्य आरोपी को भी शराब पिलाई। प्लानिंग से करण गोस्वामी को मिलेनियम प्लाजा के पास से अगवा किया। उससे फोन कर मोहसिन उर्फ मंत्री खान को बुलवाया। इससे बाद उसे भी चार पहिया वाहन में अगवा कर बबरता की थी। वाहन तेजेंद्र गुर्जर का है। ऐसे में इन दोनों आदतन अपराधियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की गई है।

इस अमानवीयता का मामला सामने आने के बाद लगभग 2 महीने पुराना एक और वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें आरोपी बनाए गए गोलू गुर्जर के साथ आधा दर्जन लोग

लाटियों से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। यह घटना 21 मई 2023 की है। जब गोलू डबरा में एक शादी समारोह में शामिल होने गया था। तब बाहर गली में खड़े कुछ लोगों से उसका विवाद हुआ। वहीं हमलावरों ने गोलू गुर्जर के ऊपर लाटियों से प्रणघातक हमला किया था। पूरी घटना के दो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। लहलुहान हालत में गोलू गुर्जर का बयान भी सामने आया है। जिसमें वह हमलावरों में मोहसिन उर्फ मंत्री खान लाला पंडित वंश पाठक सहित उनके तीन अन्य साथियों के नाम बता रहा है। इस घटना के बाद बदला लेने के लिए गोलू गुर्जर और उसके साथियों ने 30 जून को मोहसिन खान पर स्कॉपीयो जीप में हमला किया था और उसे जूते से पीटने के बाद उससे अपने पैरों के तलवे भी चटवाए थे।



राजपूत समाज ने आयोजित किया कलेक्टर का विदाई समारोह

माही की गूँज, अलीराजपुर।

जिले के कलेक्टर राघवेंद्र सिंह का स्थानांतरण आगर मालवा हो जाने पर राजपूत समाज सदस्यों ने कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के साथ ही पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक चौधरी उपस्थित रहे। राजपूत समाज के द्वारा आयोजित किया गया। जहां पर बड़ी संख्या में राजपूत समाज के समाज सदस्यगण उपस्थित रहे। अतिथियों का सर्वप्रथम राजपूती साफा पहनाकर समाज जन ने स्वागत किया गया साथ ही समाज के सदस्यों के द्वारा पुष्प माला पहना कर भी कलेक्टर के अलावा अन्य अतिथियों का स्वागत किया गया। राजपूत समाज के प्रभारी अध्यक्ष रिकेश तवर एवं सृष्टि मंडल के अध्यक्ष एडवोकेट रमण सोलंकी ने कलेक्टर को बताया कि, संस्कार धाम वाटिका में 36 प्रकार के ओषधीय पौधे हैं, जो कई बीमारी में उपयोगी है।

साथ ही कहा कि, सरल एवं सौम्य स्वभाव के धनी हैं। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह इनके कार्यकाल के दौरान इन्होंने सभी की हेल्प की है, सहयोग किया है और एक अमित छाप इस अलीराजपुर जिले में कलेक्टर राघवेंद्र सिंह जी ने छोड़ी है। इनके कार्यकाल को कोई नहीं भूल सकता है नहीं भुला जा सकता है जन हितेषी का अधिक किए गए हैं। जिले में कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने कई कार्य किए जिससे मध्य प्रदेश में जिला कई योजनाओं में प्रथम आया है। पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह एवं जिला पंचायत सीओ अभिषेक चौधरी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि, कलेक्टर के साथ में काम कर बहुत कुछ सीखने को मिला है। इनके द्वारा दिया गया अनुभव हमें आगामी दिनों में इस क्षेत्र में इस जिले में काम करने में बहुत उपयोगी साबित होगा। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि, इस जिले में काम करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत संभवना है। राजपूत समाज जनो ने यह बहुत ही अच्छा गार्डन



डेवलप किया है, यह कई ओषधीय पौधे भी हैं जो की गुणकारी है। क्योंकि मैंने यह पूर्व में आकर देखा है और सुना है कि राजपूत समाज के जो बरिष्ठ हैं, युवा हैं, महिलाएं सभी लोग इस गार्डन में सुबह-शाम आते हैं घूमने के लिए आते हैं, ओषधी पौधों का उपयोग करते हैं, इस गार्डन में आकर अपना फल लगता है, मैं आभारी हु जो

जेलर ने बदली मासूम की जिंदगी, जेल से रोज पढ़ने जाएगी कैदी की बेटी

दमोहा।

जिले के हटा उप जेल में अपने माता पिता के साथ रह रही चार वर्ष की एक मासूम बेटी अब स्कूल जाएगी। यह बच्ची एक वर्ष की उम्र में अपने माता पिता द्वारा किए गए अपराध की सजा उनके साथ जेल में रहकर काट रही है। दमोहा जिले के हटा तहसील अंतर्गत एक गांव के रहने वाले प्रहलाद लोधी और उसकी पत्नी और छुट्टी जेल में हत्या के आरोप में निरुद्ध हैं। उनके साथ उनकी बच्चे जो वर्तमान में 4 वर्ष की है, वह भी तीन वर्ष पूर्व उनके ही साथ जेल में आई थी। प्रतिदिन की भांति जेल का निरीक्षण करने के दौरान, जब हटा उप जेल के जेलर की नजर बेटी

पर पड़ी, तो उन्होंने उसे पढ़ाने का इच्छा जाहिर की। इसके बाद समस्त स्वीकृतियां लेकर उस बेटी का फटाके निजी स्कूल में दाखिला कराया गया। दाखिले के बाद अब यह बेटी रोज ही अध्ययन करने के लिए स्कूल जाएगी और छुट्टी के बाद वापस जेल आएगी। जेलर की इस पहल की सभी लोग सराहना कर रहे हैं। जेलर नागेंद्र चौधरी ने बताया कि, दस जुलाई को जेल के निरीक्षण के दौरान एक अंबोध बालिका से उनका सामना हुआ। उन्होंने

उससे पूछा स्कूल में पढ़ने जाना है, मासूम ने स्वीकृति में सिर हिला दिया, लेकिन उसे जेल से अपनी मर्जी से सीधे किसी स्कूल भेज देना जेल मैनुअल के हिसाब से उचित नहीं था। उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए जेलर ने सबसे पहले उसके माता-पिता आरती एवं प्रहलाद लोधी से उसकी सहमति प्राप्त की। इसके बाद पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए न्यायालय से अनुमति प्राप्त की और अपने खुद के बच्चों के साथ उसका नाम स्कूल में लिखवा

दिया। जेल में अपने माता-पिता के साथ बंद इस चार वर्षीय बच्ची का कल स्कूल का पहला दिन था। जेल मैनुअल के अनुसार निर्धारित समय पर उसे स्कूल भेजा जाएगा और स्कूल से वापस लाया जाएगा। साथ ही जेल में स्थित भोजनशाला से ही तैयार लंच उसके स्कूल बैग में रखा जाएगा। मासूम के माता-पिता हटा उप जेल में पिछले तीन वर्ष से हत्या के आरोप में निरुद्ध हैं। इनके परिवार में इनके अलावा किसी अन्य जिम्मेदार के ना होने के कारण भी यह बच्ची अपने माता-पिता के साथ जेल में ही बंद है।



क्षेत्र में हुई हल्की वर्षा किंतु हथिनी नदी किनारे से लगकर बह निकली



माही की गूँज, आम्बुआ।

वित्त सप्ताह से बारिश का इंतजार कर रहे कृषकों को क्षेत्र में 10 जुलाई की रात से हो रही रिमझिम वर्षा से राहत मिली है। कम बारिश के बावजूद हथिनी नदी के ऊपरी क्षेत्रों में हुई जोरदार बारिश के कारण 11 जुलाई की सुबह 9 बजे नदी में पानी की आवक बढ़ जाने से हथिनी नदी किनारे से लगकर बह निकली जिससे कृषकों में हर्ष व्याप्त है। इस वर्ष क्षेत्र में वर्षा ने लंबा इंतजार कराया लगभग 15 दिनों की देरी से आया मानसून रिमझिम बारिश लेकर आया। जबकि क्षेत्र में तेज बारिश की ज़रूरत महसूस की जा रही है। खेतों में बोया गया बीज

अंकुरित हो चुका है जिसे पानी की सख्त ज़रूरत है। इंतजार के बाद 10 जुलाई की रात रिमझिम वर्षा का क्रम जारी रहा। आम्बुआ क्षेत्र में हालांकि कम वर्षा हो रही है इसके बावजूद क्षेत्र की हथिनी नदी में 11 जुलाई की सुबह 9 बजे अचानक ही तेज बहाव देखा गया नदी क्षेत्र के ऊपरी क्षेत्र में झामझम वर्षा होने के कारण हथिनी नदी में किनारों तक जल बह निकला। जिससे जल संग्रहण क्षेत्रों में जल स्तर बढ़ेगा विशेषकर फाटा डेम में जलस्तर बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। क्षेत्र में हथिनी में बड़े जलस्तर को देखने लोग उमड़ पड़े। इस अचानक आए पानी के कारण नवीन बैराज में ऊपर तक कचरा कूड़ा तैरता दिखाई दिया।

आदिवासियों की बुनियादी सुविधाएं अभी भी अधूरी, आदिवासी पलायन करने पर मजबूर

माही की गूँज, जोबट।

जोबट विधानसभा क्षेत्र 192 की आदिवासी बहुल जोबट के मुद्दे तो बहुत हैं। मगर सबसे बड़ा मुद्दा स्थानीय स्तर पर स्थानीय रोजगार न होने से पलायन बड़ा मुद्दा है। आज भी इस क्षेत्र को बड़ी आबादी को काम के लिए अन्य प्रांतों में जाना पड़ता है। स्वास्थ्य सुविधाएं बेहद लाचार हैं तो वहीं पर स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों का भी अभाव कम है। बुनियादी सुविधाओं की बात करें तो हर मोर्चे पर अभी तक यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। यह सीट लंबे समय तक कांग्रेस का गढ़ रही है। 2003 की भगवा लहर में यहां समीकरण बदल गए और यहां पर भाजपा से विधायक माधोसिंह डवर जीत हासिल की थी। पिछले विधानसभा चुनाव (2018) में यहां कांग्रेस की कलावती भूरिया ने वापसी की थी। हालांकि कोविड के कारण तत्कालीन विधायक कलावती भूरिया का निधन हो गया था। उसके बाद यहां हुए उपचुनाव में फिर से भाजपा ने इस सत्ता पर कब्जा कर लिया और कांग्रेस के बाद यहां भाजपा प्रत्याशी

सुलोचना रावत को भी पर्याप्त अवसर मिला है। हालांकि विकास की मुख्यधारा में यह क्षेत्र अब तक नहीं आ पाया है। मुख्यमंत्री की कई घोषणाओं के बाद भी आज तक यहां न तो स्नातकोत्तर महाविद्यालय बना, न सिविल अस्पताल और न ही खेल मैदान की सौगात मिल सकी। ऐसा नहीं है कि क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हुए। पक्के मकान, सड़कें, बिजली, पानी आदि सुविधाएं पहले से बेहतर जरूर हैं, लेकिन इनमें भी काफी सुधार की ज़रूरत है। विधानसभा के नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण बड़ी समस्या है। साथ ही जोबट में शासन द्वारा लाखों रुपये खर्च कर बनाई गई सज्जी मंडी आज भी वीरान पड़ी है और कहीं वर्षों से बनी अनाज मंडी भी वीरान पड़ी हुई है। इन दोनों मंडी में अभी तक ना ही कांग्रेस सरकार ने कुछ किया है और न भाजपा सरकार ने कुछ किया है। जिसका खामियाजा भोले भाले आदिवासी किसान लोगों को भरना पड़ रहा है। कई बार कार्रवाई करने के बाद भी अतिक्रमणकारी और स्थानीय सज्जी विक्रेता उस का मस नहीं होता दिखा है। जिसके कारण आए दिन

न तो गांवों की स्थिति सुधरी न ही शहर की



नगरीय क्षेत्र के नगरवासियों को जाम जैसी समस्या से झुझना पड़ता है। स्वास्थ्य सेवाएं लाचार होने के चलते गंभीर बीमारी के लोगों को सीमावर्ती राज्य गुजरात या अन्य प्रदेश के बड़े शहरों की ओर रुख करना पड़ता है। आकस्मिक दुर्घटना होने पर मरीजों को अन्य राज्य में रेफर कर दिया जाता है। तत्कालीन इलाज न मिलने से मरीज कई बार रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। मतांतरण इस क्षेत्र में तेजी से हो रहा है। जिस

पर भी भाजपा की सरकार रोक नहीं लगा पाई है। हालांकि वर्तमान विधायक की ओर से विकास को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष इन दावों को खोखला बता रहा है। **विधायक ने गिनाई उपलब्धियां...** वर्तमान विधायक सुलोचना रावत ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि, 1.43 करोड़ रुपये के 88 पानी टैंकर वितरित किए। 21.20 करोड़ रुपये के बैराज के निर्माण हुए। 4 सीएम राइज स्कूल स्वीकृत कराए गए। 300 करोड़ रुपये के 9 नए छात्रावास निर्माण। 80 करोड़ की लागत से 92 किमी सड़क निर्माण। 619 हितग्राहियों को 32.57 लाख रुपये स्वेचनुदान राशि के रूप में स्वीकृत किए गए। 700 करोड़ रुपये के विद्युतीकरण कार्य मंजूर की गए। **स्थिति वही ढाक के तीन पात** वहीं जोबट विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी और पलायन की

समस्या आज भी विद्यमान है। योजनाओं के सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं होने से आम जनता परेशान है। एक करोड़ रुपये की लागत से जोबट में बने नए बस स्टैंड स्थित नगर परिषद की दुकानें नीलाम होने के बाद भी सिर्फ एक दुकान को छोड़कर सभी दुकानें बंद पड़ी हैं। जिसके कारण यहां हर समय विरानी नजर आती है। साथ ही मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि, 1.43 करोड़ रुपये के 88 पानी टैंकर वितरित किए। 21.20 करोड़ रुपये के बैराज के निर्माण हुए। 4 सीएम राइज स्कूल स्वीकृत कराए गए। 300 करोड़ रुपये के 9 नए छात्रावास निर्माण। 80 करोड़ की लागत से 92 किमी सड़क निर्माण। 619 हितग्राहियों को 32.57 लाख रुपये स्वेचनुदान राशि के रूप में स्वीकृत किए गए। 700 करोड़ रुपये के विद्युतीकरण कार्य मंजूर की गए। **स्थिति वही ढाक के तीन पात** वहीं जोबट विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी और पलायन की

